सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 49, नई दिल्ली । बुधवार, 01 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नही खोना आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है।

03 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली CM की गिरफ्तारी पर ED से पूछे 5 सवाल
06 'पुनर्वितरण' की कवायद और चुनावी पारा
08 मुख्यमंत्री नबीन पटनायक हिंजिलिकाटू से अपना नामांकन दाखिल किया

15-20 दिन बंद रहेगा नारायणा फ्लाई ओवर का धौला कुआं से मायापुरी तक का कैरिजवे, पुलिस की इन मार्गों पर जाने की सलाह

बुधवार से नारायणा फ्लाई ओवर का धौला कुआं से मायापुरी तक का कैरिजवे मरम्मत किया जाएगा। मरम्मत कार्य के चलते धौला कुआं से मायापुरी तक का कैरिजवे यातायात के लिए बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान धौला कुआं की ओर यातायात की आवाजाही के लिए मायापुरी से धौला कुआं तक कैरिजवे चालू रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए तीन वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं।

संजय बाटला

नई दिल्ली। बुधवार से नारायणा फ्लाई ओवर का धौला कुआं से मायापुरी तक का कैरिजवे मरम्मत किया जाएगा। मरम्मत कार्य के चलते धौला कुआं से मायापुरी तक का कैरिजवे यातायात के लिए बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान, धौला कुआं की ओर यातायात की आवाजाही के लिए मायापुरी से धौला कुआं तक कैरिजवे चालू रहेगा।

यातायात पुलिस ने लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए तीन वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं। मरम्मत का यह कार्य 15 से 20 दिन तक चल सकता है, जिसके चलते यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी हैं।

धौला कुआं से आने वाले और मायापुरी की ओर जाने वाले इन मार्गों का करें प्रयोग

धौला कुआं से वंदे मातरम मार्ग लें, प्रोफेसर रामनाथ विज मार्ग पर बाएं मुड़ें, रतनपुरी चौक से बाएं मुड़ें, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पर, लोहा मंडी टी-प्वाइंट से गोस्वामी गिरधारी लाल मार्ग पर बाएं मुड़ें और नारायणा टी-प्वाइंट से दाएं मुड़ें रिंग रोड पर मायापुरी के लिए।

धौला कुआं से करिअप्पा मार्ग लें, फिर शहीद भगत सिंह मार्ग (जेल रोड) से लाजवंती चौक तक, सतगुरु राम सिंह मार्ग पर दाएं मुड़ें और माया पुरी चौक (रिंग रोड) तक जाएं।

दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन से मौड मार्ग लें, फिर करिअप्पा मार्ग पर दाएं मुड़ें, फिर शहीद भगत सिंह मार्ग (जेल रोड) से लाजवंती चौक तक, सतगुरु राम सिंह मार्ग पर दाएं मुड़ें मायापुरी चौक (रिंग रोड) तक।

यातायात पुलिस ने आम जनता से की ये अपील

यातायात पुलिस ने लोगों को सड़क किनारे वाहन पार्क नहीं करने की सलाह दी है क्योंकि इससे यातायात के सामान्य प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही अस्पताल, आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले वाहन चालकों से पहले से ही प्रयाप्त समय लेकर रूट चैक कर निकलने की सलाह दी है।

पानी पानी चिल्लाते रहे रेल यात्री स्टाफ की बेरूखी आई सामने

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। जहां एक तरफ भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, जैसी ट्रेनों को पटरी पर उतारने के हवा महली ख्वाब दिखा रहा है तो वहीं खराब गुणवत्ता वाले भोजन ,अस्वच्छ शौचालयों ,खराब स्टाफ सेवा और भीड-भाड वाली ट्रेनों से यात्रियों को हो रहे रोज-ब-रोज के कडवे अनुभवो के कई विडियो सोशल मीडिया में सामने आते रहते हैं। इसी कडी में हाल ही में एक विडियो सामने आया है ,जिसमें एक यात्री को पानी की बोतल लेने के लिए ट्रेन में खासी मशक्कत करनी पडी।

उस शख्स ने आप बीती का विडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अभिनय नाम के एक्स यूजर ने अपनी ट्रेन यात्रा का वीडियो शेयर किया। विडियो के मुताबिक भारतीय रेलवे गर्मी के भोपाल के दौरान प्यासों को पानी तक मयैस्सर नहीं कर रहा है ।वीडियो में एक नहीं पांच लोगों को पानी चाहिए था,शख्स के मुताबिक पानी-पानी की त्राहि के चलते वह दरवाजे को लगातार ढकेल रहा है। हाथों में बोतल लिये दरवाजे को तोडने की मुद्रा में तांडव कर रहा है। इतने के बाद भी अंदर बैठा स्टाफ पानी देने से मना कर रहा है ।स्टाफ का रहा रचाया जवाब मिलता है कि पानी समय से ही मिलता है 11 बजे के बाद पानी उपलब्ध नहीं है। इस विडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स रेलवे की घटिया नवाजी पर कमेंट दे रहे। यूजर्स लिख रहे है कि भारतीय रेल की यह कैसी सेवा है,पूरी तरह से डाउन ग्रेड कर दिया है। शोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे की हो रही किरकिरी से परेशान हो उक्त यूजर्स की पोस्ट के जवाब में भारतीय रेलवे ने इस असुविधा के लिए माफी मांगी ।रेलवे ने बाकायदा यूजर्स अभिनव को आगे की सहायता के लिए अपना पी एनबीएआर नंबर सम्पर्क विवरण सांझा करने के लिए कहा।

@IRTC official

सड़क सुरक्षा पाठशाला - नशे की जगह स्वास्थ्य का चयन: "नारियल पानी वर्सेज मदीरा" नशे पर तंदुरुस्ती की जीत

दैनिक जीवन की भागदौड़ में, हमें अक्सर ऐसे विकल्पों का सामना करना पड़ता है जो हमारी भलाई पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इन विकल्पों में से शायद फिट रहने या नशीले पदार्थों का सेवन करने के बीच के निर्णय से अधिक कठोर कोई भी नहीं है। हमारे देश सहित दुनिया के कई कोनों में, दोनों विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं, जो अक्सर सड़क के किनारे स्टालों पर एक साथ पाए जाते हैं। हालाँकि, इन विकल्पों की गंभीरता को समझना, विशेष रूप से युवाओं के बीच, महत्वपूर्ण है।

हाल के वर्षों में, सामाजिक मानदंडों और साथियों के दबाव के कारण युवाओं में शराब की खपत तेजी से बढ़ी है। फिर भी, अत्यधिक शराब के सेवन के परिणाम अच्छी तरह से प्रलेखित हैं, जिनमें बिगड़ा हुआ निर्णय और मोटर कौशल से लेकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि यकृत की क्षति और लत शामिल हैं। इन जोखिमों के बावजूद, शराब सामाजिक परिवेश में व्यापक उपस्थिति बनाए हुए है, अक्सर ग्लैमराइज़ और सामान्यीकृत होती है, खासकर युवा जनसांख्यिकीय के बीच।

दूसरी ओर, एक प्राकृतिक विकल्प मौजूद है जो न केवल प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से भी भर देता है: नारियल पानी। साधारण नारियल से तैयार किया गया यह ताज़ा पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि असंख्य स्वास्थ्य लाभों का भी दावा करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है, पाचन में सहायता करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, यह ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो इसे शराब के हानिकारक प्रभावों के बिना ताज़ा पिक-मी-अप चाहने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

शराब के स्थान पर नारियल पानी का चयन करके, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए सचेत निर्णय ले सकते हैं। यह विकल्प मात्र जलयोजन से आगे तक फैला हुआ है; यह आत्म-देखभाल और जिम्मेदार निर्णय लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करता है, शराब की खपत से जुड़े सांस्कृतिक मानदंडों को नया आकार देता है और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है।

हालाँकि, जिम्मेदारी केवल व्यक्तियों पर नहीं है। सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और समुदायों को भी शराब के दुरुपयोग से जूझ रहे लोगों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने और सहायता प्रणाली प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सचेतनता और संयम की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम व्यक्तियों को सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बना सकते हैं जिससे न केवल उन्हें बल्कि पूरे समाज को भी लाभ होगा।

प्रलोभनों और दबावों से भरी दुनिया में, जब आप सड़क पर हों और गाड़ी चला रहे हैं, शराब के बजाय नारियल पानी का विकल्प जीवन शक्ति, स्पष्टता और दीर्घायु के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आइए हम मदीरा के बजाय एक नारियल उठाएं, एक ऐसे भविष्य की शुरुआत करें जहां नशे पर तंदुरुस्ती की जीत हो।

-अंकुर शरण

पर्यावरण पाठशाला : श्रम का सम्मान: समाज की रीढ़ को एक श्रद्धांजलि

ऐसी दुनिया में जहां प्रगति को अक्सर तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में मापा जाता है, वहां रुकना और अथक श्रम शक्ति के अमूल्य योगदान को पहचानना आवश्यक है। जैसे ही हम मजदूर दिवस मनाते हैं, हम उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनका समर्पण और कड़ी मेहनत हमारे समाज की नींव बनाती है।

शहर की हलचल भरी सड़कों से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक, मजदूर गुमनाम नायक हैं जो सभ्यता के गियर को घुमाते रहते हैं। वे चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड में कड़ी मेहनत करते हैं, अक्सर अनदेखा और अनसुना, फिर भी उनके प्रयास हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में गूंजते हैं।

उस निर्माण श्रमिक के बारे में सोचें जो हमारे शहर के क्षितिज को आकार देने वाली ऊंची गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करता है, या उस किसान के बारे में सोचें जो हमारी मेजों पर भोजन रखने के लिए खेतों में खेती करता है। उन नर्सों और देखभाल करने वालों पर विचार करें जो आराम और उपचार प्रदान करते हैं, और उन शिक्षकों पर भी विचार करें जो अगली पीढ़ी को ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति हमारे समाज का ताना-बाना बुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

फिर भी, उनके अपरिहार्य योगदान के बावजूद, मजदूरों को अक्सर चुनौतियों और अन्याय का सामना करना पड़ता है। कई लोग अपने परिवार के भरण-पोषण और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के नाम पर लंबे समय तक काम करने, खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों और अल्प वेतन का सामना करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल उनके बलिदानों को पहचानें बल्कि उनके अधिकारों और कल्याण की वकालत भी करें।

जैसा कि हम मजदूर दिवस मनाते हैं, आइए हम दुनिया भर के लाखों मजदूरों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करें। आइए हम उनकी गरिमा और उनकी कला के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को स्वीकार करें। क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां प्रत्येक श्रमिक के साथ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए और जहां उनके श्रम को वास्तव में महत्व दिया जाए और सम्मानित किया जाए।

इसलिए, जब आप लंबे सप्ताहांत का आनंद लेते हैं या प्रियजनों के साथ इकट्ठा होते हैं, तो उस मेहनत और पसीने पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें जो उस दुनिया के निर्माण में लगा है जिसमें हम रहते हैं। आइए हम अतीत और वर्तमान के मजदूरों का सम्मान करें और उनकी विरासत हमें सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा

देश में शिव के जो बारह ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में मान्यता है कि अगर सुबह उठकर सिर्फ एक बार भी बारहों ज्योतिर्लिंगों का नाम ले लिया जाए तो सारा काम हो जाता है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है। शिव पुराण की कथा के हिसाब से प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी सत्ताईस कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी। सत्ताईस कन्याओं का पति बन के चंद्रमा बेहद खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थीं। लेकिन यह प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। यह बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। जब राजा दक्ष को यह बात फिर पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए। उनसे कहा कि मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं। लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का असर नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी रौशनी जाती रही। ये देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ के इसी जगह पर आना था। भगवान शिव का तप करना था और उसके बाद ब्रह्मा जी के हिसाब से भगवान शिव के प्रकट होने के बाद वो दक्ष के शाप से मुक्त हो सकते थे। इस जगह पर चंद्रमा आए। भगवान वृषभध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया। फिर छह महीने तक शिव की कठोर तपस्या करते रहे। चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव खुश हुए। उनके सामने आए और वर

मांगने को कहा। चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भगवन अगर आप खुश हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने शाप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा जरूर। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया उसे देखकर चंद्रमा न ज्यादा खुश हो सके और न ही उदास रह सके। लेकिन शिव ने ऐसा किया क्या। चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न थे। उन्हें वर देना चाहते थे लेकिन संकट देखिए। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया है वो भी कोई साधारण हस्ती नहीं थे। असमंजस था ऐसा असमंजस जिसमें भगवान शिव भी पड़ गए थे। खैर, शिव एक रास्ता निकालते हैं। चंद्रमा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं एक माह में जो दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे। लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होओगे। ये पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का जिसमें एक पक्ष में वो बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से भी चंद्रमा काफी खुश हो गए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया उनकी स्तुति की। यहां पर एक बड़ा अच्छा रहस्य है। अगर आप साकार और निराकर शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे। और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहां सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहां से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। जब शिव सोमनाथ के रूप में यहां स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी तो पूजा की ही, चंद्रमा को भी नमस्कार किया। क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का ये स्वरूप इस जगह पर मौजूद है। समय गुजरा। इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में कथा है कि जब शिव सोमनाथ के रूप में यहां निवास करने लगे तो देवताओं ने यहां एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है। इसलिए जो भी उस कुंड में स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसे हर तरह के रोगों से निजात मिल जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि असाध्य से असाध्य रोग भी कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन एक विधि है जिसको मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे उस कुंड में लगातार छह माह तक स्नान करना होगा। ये महिमा है सोमनाथ की। शिव पुराण में ये भी लिखा है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। इस तीर्थ पर और भी तमाम मुरादें हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। क्योंकि ये तीर्थ बारह ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में काठियावाड़ नाम की जगह पर स्थित है। इस मंदिर में जो सोमनाथ देव हैं उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को शिव ने शाप मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव की पूजा की थी, उसी विधि से आज भी सोमनाथ की पूजा होती है। अगर आप शिवरात्रि की रात यहां महामृत्युंजय मंत्र का महज एक सौ आठ बार भी जाप कर देते हैं तो वो सारी चीजें आपको हासिल हो सकती जिसके लिए आप परेशान हैं। यह है इस धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव पुराण में ये कथा महर्षि सूरत जी ने दूसरे ऋषियों को सुनाई है। जो जातक इस कथा को ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनाते हैं उनपर चंद्रमा और शिव दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता के वाहक हैं। उनके खुश होने से इंसान मानसिक तनाव से दूर होता है। और शिव इस जगत के सार हैं। उनके खुश होने से जीवन के सारे मकसद पूरे हो जाते हैं।

कलयुग में सनातन धर्म की जड़ो को सींचने का काम किया, जानें

स्व. श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार जी जिन्होंने गीता_प्रेस गोरखपुर की स्थापना की ओर कलयुग में सनातन हिन्दुओ के घर घर मे वैदिक धर्म ग्रंथों, शास्त्रौ को पहुचाने का काम किया। आज हिन्दुओ के घर मे जो सनातन शास्त्र पहुच रहे है वो स्व श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की देन है। वास्तव में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हनुमान ही थे जब हिन्दू समाज अपने ज्ञान, विज्ञान, गौरव को भुल अंग्रेजी सभ्यता का दास बन रहा था, तब इन्होंने हनुमान की भांति संजीवनी रुपी गीता_प्रेस गोरखपुर (सनातन शक्तिपुंज) की स्थापना कर जो सनातनियों को जड़ से जोड़े रखने का भगीरथी प्रयास किया। उसके लिए हिन्दू समाज हमेशा इनका ऋणी रहेगा। ऐसे धर्मरक्षक महावीरो को नई पीढ़ी द्वारा भूलना सिर्फ गलती नही महापाप होगा। इन लोगो ने

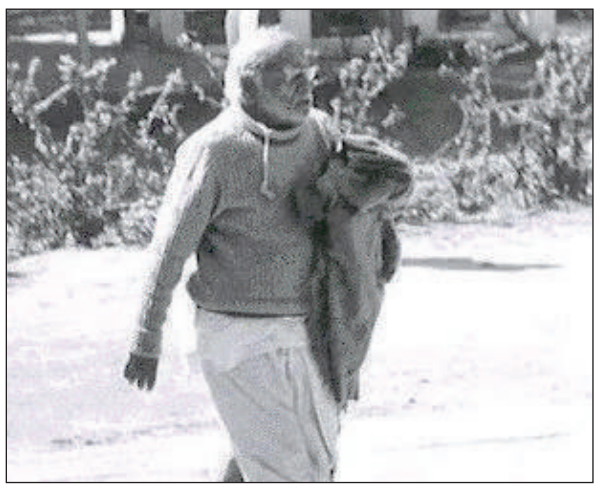

अभावो में रहकर भी कैसे संस्थान खड़े किए होंगे जो सम्पूर्ण विश्व मे वैदिक धर्म ग्रंथ शास्त्र पहुचाने वाले सबसे बडे हिन्दू संस्थान बनकर उभरे। ना पैसा ना संसाधन फिर भी हिंदू समाज की आने वाली पीढ़ियों तक शास्त्रो का अमर ज्ञान पहुचाने के लिए अपना सब कुछ वार दिया।

वल्लभाचार्य : पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक

भारत अनेकता में एकता रखने वाला देश है। यहां पर विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियों के लोग वास करते हैं। यहां तो प्रकृति में भी विविधता देखने को मिलती है। कहीं बहुत तेज गर्मी तो कहीं कडक़ड़ाती ठंड, कहीं दूर-दूर तक सुनहरा रेगिस्तान तो कहीं पहाड़ ही पहाड़। इन्हीं भिन्नताओं में जो एक चीज हमें बांधे रखती है, वह है हमारी भारतीयता और भारतीयों का अध्यात्म से बहुत गहरा नाता रहा है। अध्यात्म भी हमारे यहां भिन्न प्रकार का मिलता है, कई प्रकार की भक्ति मिलती है। कोई ईश्वर के साकार यानी सगुण रूप को मानता है तो कोई निराकार यानी निर्गुण रूप को।

जब भी भक्ति या अध्यात्म की बात होती है तो याद आती है भारत में भक्ति की अविरल धाराओं की जो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, आचार्य निंबार्क और वल्लभाचार्य से होती हुई अभी तक नए-पुराने रूपों में बहती चली आ रही हैं। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के वह आधारस्तंभ हैं जिन्होंने साधना के लिए पुष्टिमार्ग से परिचित करवाया, जिन्होंने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज बनाया। पुष्टिमार्ग के इस प्रवर्तक की जयंती वैशाख के पावन मास में मनाई जाती है। माना जाता है कि वैशाख मास की कृष्ण एकादशी को कृष्णभक्ति के मार्ग को दिखाने वाले सूरदास को लीलाधर की लीलाओं से परिचित कराने वाले वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म विक्रमी संवत 1535 में दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्राम, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट चंपारण है, में तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी के घर हुआ। उनकी माता का नाम इल्लमागारू था। उनके जन्म को लेकर एक किंवदंती भी प्रचलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि उनका जन्म माता इल्लमागारू के गर्भ से अष्टमास में ही हो गया था। उनको मृत जान माता-पिता ने छोड़ दिया जिसके पश्चात श्री नाथ जी ने स्वयं स्वप्न में माता इल्लमागारू को दर्शन दिए और कहा कि स्वयं श्री नाथ जी उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं।

संस्कारशाला - हम व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है : प्रियंका श्रीवास्तव

हम अक्सर समय के बारे में शिकायत करते हैं हमारे पास समय के अलावा सब कुछ है आइए प्रभावी समय प्रबंधन की योजना बनाएं

आपके समय प्रबंधन को सर्वोत्तम बनाने में मदद के लिए यहां कुछ युक्तियां और तकनीकें दी गई हैं :

कार्यों को प्राथमिकता दें: पहचानें कि क्या तत्काल करने की आवश्यकता है और क्या करने की प्रतीक्षा की जा सकती है। पहले उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर ध्यान दें।

स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें: अपनी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने और अपनी प्रगति को मापने के लिए प्रत्येक दिन या सप्ताह के लिए विशिष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य परिभाषित करें।

कार्यों को छोटे-छोटे चरणों में बाँटें: कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय भागों में बाँटने से वे कम कठिन और निपटने में आसान हो जाते हैं।

समय अवरोधन का उपयोग करें: विभिन्न गतिविधियों के लिए समय के विशिष्ट ब्लॉक आवंटित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निर्बाध समय समर्पित करते हैं।

विकर्षणों को कम करें: सोशल मीडिया, ईमेल या सूचनाओं जैसे सामान्य विकर्षणों को पहचानें और केंद्रित कार्य अवधि के दौरान उन्हें कम से कम करें।

ना कहना सीखें: अपने आप को अति समर्पित न करें। अपने आप को बहुत अधिक फैलाने से बचाने के लिए अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों और गतिविधियों के बारे में चयनात्मक रहें।

जब संभव हो तो कार्य सौंपें: यदि आपके पास ऐसे कार्य हैं जो दूसरों द्वारा किए जा सकते हैं, तो उन्हें अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए अपना समय खाली करने के लिए सौंपें।

नियमित ब्रेक लें: ब्रेक फोकस और उत्पादकता बनाए रखने में मदद करता है। रिचार्ज करने और बर्नआउट से बचने के लिए कार्यों के बीच छोटे ब्रेक शेड्यूल करें।

टूल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करें: अपने शेड्यूल को व्यवस्थित करने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए उत्पादकता ऐप्स, कैलेंडर और कार्य प्रबंधन टूल का उपयोग करें।

प्रतिबिंबित करें और समायोजित करें: क्या काम कर रहा है और क्या सुधार की आवश्यकता है, इसकी पहचान करने के लिए नियमित रूप से अपनी समय प्रबंधन रणनीतियों की समीक्षा करें और तदनुसार समायोजित करें।

इन तकनीकों को लागू करने से आपको अपना समय प्रबंधन अनुकूलित करने और अपने दिन का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिल सकती है।

अंधेरे को भूल जाओ

चक्रवात जा चुका और अब तुम अपने केंद्र पर हो, केंद्रित जैसे कभी तुम पहले नहीं थे और अगर एक बार तुम चीजों को अपने से ही होने की कला जान लो तब तुम वह मास्टर कुंजी पा सकोगे, जिससे अपने भीतर के द्वार खोले जा सकते है। फिर चाहे जो भी स्थिति हो, उसे होने दो, उसे टालो मत। अगर तीन महीनों के लिए तुम बिलकुल एकांत में रह सको, पूर्ण मौन में, किसी भी चीज का विरोध न करते हुए, प्रत्येक चीज को बिना किसी विरोध के घटित होते देखते हुए, चाहे जो भी हो, तब तीन महीनों के भीतर ही सब पुराना विदा हो जाएगा और नया उभरने लगेगा। पर इसका रहस्य यही है कि उसे होने दो। चाहे जितना भी डरावना और पीड़ादायक लगे, चाहे फिर मौत या उस जैसा ही खतरनाक लगे। बहुत से क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा अगर तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम पागल हो जाओगे फिर बिना किसी इच्छा के भी तुम कुछ न कुछ करने लगोगे। तब तुम यह भी समझ सकते हो कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, पर तुम नियंत्रण में नहीं रह पाते और कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हो। यह ऐसा ही है, जैसे कि रात को तुम किसी अंधेरी गली से गुजर रहे हो आधी रात को, और तुम्हें डर लगने लगे क्योंकि वहां चारों ओर सुनसान हो और रात अंधेरी और गली अनजानी हो, तब तुम सीटी बजाना शुरू कर देते हो। सीटी बजाने से क्या होता है? तुम जानते हो इससे कुछ भी नहीं होगा। तब तुम कोई गीत गाना शुरू कर देते हो, तुम यह भी जानते हो कि गाने से भी कुछ नहीं होने वाला, इससे अंधेरा नही मिटने वाला, तुम अकेले ही रहोगे, लेकिन इससे ध्यान बंटता है। अगर तुम सीटी बजाना शुरू करते हो, तो सीटी बजाने से तुम्हें साहस मिलता है और तुम अंधेरे को भूल जाते हो। तुम्हारा मस्तिष्क सीटी बजाने लगता है और तुम्हें अच्छा लगने लगता है। कुछ भी नहीं हुआ। गली वही है, अंधेरा और खतरा भी वही है, फिर भी कुछ है, वह यह कि अब तुम ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। सब कुछ वही है, पर अब तुम कुछ कर रहे हो। तुम किसी भी नाम का जाप करने लगते हो, किसी मंत्र का, यह भी किसी सीटी बजाने जैसा ही है। यह तुम्हें शक्ति देगा पर यह शक्ति खतरनाक है, यह शक्ति फिर से मुसीबत बन सकती है, क्योंकि यह शक्ति फिर से तुम्हारे पुराने अहंकार को निर्मित करेगी। तब तुम उसे पुनर्जीवित कर रहे हो। भय के पार जाने के लिए उसका सामना करना होगा। पीड़ा को खत्म करने के लिए उसका सामना करना होता है। और अधिक प्रामाणिक ढंग से सामना करने के लिए सीधे ही उसकी ओर देखना, चीजों को सीधे ही ऐसा देखना, जैसी वे हैं, जल्दी ही सब अपने से होने लगेगी। इसमें समय लगता है क्योंकि तुम्हारी प्रामाणिकता सघन नहीं है।

मोबाइल की आभासी दुनिया में खोता बालमन

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुए एक अध्ययन में भी साफ हो गया है कि शहरी बच्चें, गेमिंग, सोशियल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म के आदी होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि बालक मन संवेदनहीन होता जा रहा है।

सोशल मीडिया पर आये दिन इस तरह की तस्वीर देखने को मिल जाएगी जिसमें ड्राइंग रुम में तो परिवार के लगभग सभी सदस्य बैठे हैं पर उनके बीच किसी तरह के संवाद की बात करना ही बेमानी होगा। सभी अपने-अपने स्थान पर अपने मोबाइल फोन में खोये मिलेंगे। खोये होने का मतलब साफ है कि कोई गेमिंग कर रहा होगा तो कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाट्सएप या इसी तरह के किसी दूसरे एप पर व्यस्त होगा। सवाल साफ है कि जो हम देखेंगे उसमें हमें पसंद भी वोही आएगा जो अधिक ग्लेमरस होगा और यही कारण है कि गेमिंग, चेटिंग या फिर रील्स बनाने देखने में बच्चों से बड़े तक व्यस्त मिलेंगे। इसके साथ ही गेमिंग जहां बच्चों बड़ों को लालच दिखाकर एक तरह से जुआरी बना रही हैं वहीं कुछ गेम तो इस कदर हानिकारक रहे हैं कि उन्हें फॉलों करते करते बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। सोशल मीडिया, ओटीटी व गेमिंग के साथ ही गूगल बाबा सहित खोजी चैनलों, डिजिटल प्लेटफार्म खोजी सामग्री तो कोई समाचार देखते-देखते ही कितने तरह के विज्ञापन सामने आ जाते हैं उनमें कई बार तो लगभग प्रोन जैसी सामग्री होने के बावजूद मजे से परोसी जाती रहती है और उसे बेन करने या सेंसर करने का कोई सिस्टम नहीं होने से उसका दुष्प्रभाव साफ देखा जाता है। भले ही सरकार द्वारा इस तरह के चैनलों, प्लेटफार्म, एप आदि पर रोक लगाने के लाख दावें किये जाते हो पर साफतौर से इस तरह की सामग्री आम है। इसके साथ ही इन प्लेटफार्मों पर परोसी जाने वाली सामग्री बच्चों तक नहीं पहुंचे या बालमन पर को प्रदूषित नही करें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। जब इन प्लेटफार्मों पर हिंसा, यौन सामग्री, गेमिंग, संवेदनहीनता, तनाव, आत्महत्या या बदले की भावना प्रेरित करने वाली सामग्री परोसी जाएगी तो उसका प्रभाव से नकारा नहीं जा सकता। दरअसल यह विश्वव्यापी समस्या हो गई है और इसका समाधान समय रहते नहीं खोजा गया तो इसके जो दुष्परिणाम आएंगे व आने लगे हैं वे समाज के लिए भयावह होंगे, इस खतरे को समझना होगा।

तस्वीर का एक पक्ष यह भी है कि एक दूसरे से तत्काल संवाद कायम करने का माध्यम स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर परोसी जाने वाली सामग्री का सर्वाधिक दुष्प्रभाव बालक मन पर पड़ रहा है। तकनीक का इस तरह का दुष्प्रभाव संभवतः इतिहास में भी पहले कभी नहीं रहा है। दरअसल आज हम हर समस्या का समाधान स्मार्टफोन और इंटरनेट को मानने लगे हैं। बच्चा रो रहा है या किसी बात के लिए जिद कर रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है तो माताएं या परिवार के कोई भी सदस्य बच्चें को चुप कराने या मनबहलाव और खास यह कि बच्चे को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल संभला देते हैं। जबकि मोबाइल के दुष्प्रभाव हमारे सामने आने लगे हैं। अमेरिका में पिछले दिनों हुए एक सर्वे में सामने आया कि मोबाइल फोन, टेबलेट, वीडियो गेम या अन्य इस तरह के साधन के उपयोग से बच्चे गुस्सेल होते जा रहे हैं। बच्चों द्वारा स्कूल में गोलीबारी सहित एक दूसरे से मारामारी-हाथापाई व इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। मारधाड़, हमेशा गुस्से में रहने, तनाव में रहने और जिद्दी होना आज आम होता जा रहा है।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुए एक अध्ययन में भी साफ हो गया है कि शहरी बच्चें, गेमिंग, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म के आदी होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि बालक मन संवेदनहीन होता जा रहा है। हमेशा तनाव, डिप्रेशन, आक्रामकता, गुस्सेल, बदले की भावना आदि आम है। ऐसे में मनोविज्ञानियों के सामने नई चुनौती आ जाती है। यह असर कमोबेस लड़कों और लडकियों दोनों में ही समान रुप से देखा जा रहा है। यह कोई हमारे देश की समस्या हो, ऐसा भी नहीं हैं अपितु दुनिया के लगभग सभी देशों में यही हो रहा है। अमेरिका में किये गये एक अध्ययन में भी यही उभर कर आया है। कोई दो राय नहीं कि विकास समाज की

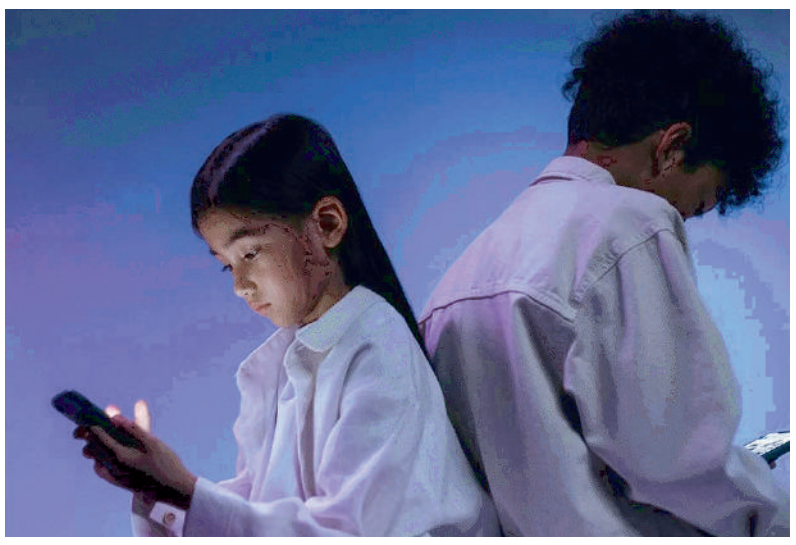

आवश्यकता है। स्माटफोन व इंटरनेट की दुनिया का अपना महत्व है। पर इनके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। प्लेटफार्मों पर चाइल्ड लोक की बात भी की जाती है पर चाइल्ड लोक कितना कारगर है यह हम सब अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि मोबाइल फोन, टेब, कम्प्यूटर, सोशल मीडिया प्लेटफार्म आदि के फीचर्स व उपयोग का तरीका बड़ों से ज्यादा बच्चों को आता है। यहां तक कि प्ले ग्रुप के बच्चें को भी यह जानकारियां होने लगी है। ऐसे में इन पर परोसी जाने वाली सामग्री को सेंसर करने या इससे बच्चों और बालपन को दूर रखने की बात बेमानी होती जा रही है। समाज विज्ञानियों, मनोविश्लेषकों, चिकित्सकों यहां तक शिक्षाविदों के सामने यह गंभीर चिंतनीय चुनौती सामने आ रही है।

आज बच्चे के सामने दो विकल्प एक मोबाइल फोन या सोशल मीडिया पर सफरिंग और दूसरा परिवार के साथ गप्पे लड़ाना या आउटडोर गेम्स जैसा विकल्प होगा तो बच्चे की पहली पसंद मोबाइल फोन व सोशल मीडिया पर सफरिंग ही होती जा रही है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है और दूसरा यह कि गरीब हो या अमीर सभी घर परिवारों के हालात लगभग यही है। दरअसल आज समय के बदलाव को इस तरह से समझा जा सकता है कि तीन से चार दशक पहले मोहल्ले में एक फोन होता था, ट्रंक काल में तो घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी वहीं फिर एसटीडी का युग आया और एसटीड़ी बूथों का अंबार लग गया उसके बाद पेजर युग को अलग कर भी दिया जाये तो मोबाइल युग ने घर-घर ही नहीं अपितु परिवार के लगभग सभी सदस्यों तक पहुंच बना ली है। ऐसे में इसके लाभ के साथ ही साइड इफेक्ट जो हमारे सामने आ रहे हैं उनका समाधान खोजना भी सबका दायित्व हो जाता है। बच्चें को चुप कराने से लेकर उसे व्यस्त रखने तक के लिए मोबाइल की घुट्टी पिलाई जाने लगी है और लोरी की जगह मोबाइल ने ले ली है तो फिर हमें बालमन पर इसके पड़ रहे दुष्प्रभाव से दो चार होने के लिए तैयार रहना होगा। देखा जाए तो पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदल गया है। एकल परिवार, आने वाले समय में चाचा-चाची, मौसा मौसी या इसी तरह के रिश्तों की तलाश आदि सामने आने लगी है। शादी विवाह आदि पारिवारिक फंक्शन तक अब औपचारिक होते जा रहे हैं। बारात के समय पहुंचना, खाना खाना, लिफाफा थमाना तक रिश्ते सीमित हो गए हैं। ऐसे में समाज के सामने गंभीर समस्याएं आती जा रही है। ऐसे में मोबाइल या सोशल मीडिया प्लेटफार्म आने वाली पीढ़ी को कहां ले जाएंगे यह भयावह तस्वीर कल्पना में नहीं अपितु हमारे सामने आती जा रही है। समय रहते विकास और विनाश के बीच कोई रास्ता तलाशना ही होगा।

आजादी... टाइमिंग और अरविंद केजरीवाल : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली CM की गिरफ्तारी पर ED से पूछे 5 सवाल

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई दूसरे दिन जारी रखते हुए दो जजों की बेंच ने केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलीलें देर तक सुनीं। फिर ईडी से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत कई सवाल किए हैं। इनके जवाब जांच एजेंसी को आने वाले शुक्रवार तक देना है।

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल किया। अदालत ने पूछा आपने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की इसका जवाब दें।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने एएसजी एसवी राजू से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए पूछा, आजादी बहुत जरूरी चीज है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।

सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने केजरीवाल के वकील को अपनी दलील रखने के लिए एक घंटे का समय दिया। केजरीवाल के वकील की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पांच सवाल पूछे-

जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के मामले में किसी कुर्की के न होने का हवाला देते हुए ईडी से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा क्या बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के विजय मदनलाल चौधरी या अन्य मामले में जो कुछ भी कहा गया है, उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है?

बेंच ने ईडी से ये सवाल भी किया कि केजरीवाल के मामले में पीएमएलए की धारा 19 कैसे लागू किया जाएगा? कोर्ट ने कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका देने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दे रहे हैं। अगर वह जमानत के लिए आते हैं तो उन्हें पीएमएलए की धारा 45 के तहत उच्च सीमा का सामना करना पड़ेगा?

अदालत ने ईडी से ये भी पूछा कि मनीष सिसोदिया के जजमेंट में दो भाग हैं- एक इन्हें फेवर करता है और दूसरा इनके हक में नहीं है। केजरीवाल का केस किस हिस्से में आता है?

अदालत ने ये भी पूछा कि कार्यवाही शुरू होने के बीच का अंतराल और बीच-बीच में लगातार जो शिकायतें फाइल की जा रही हैं। इन सबके अपने नतीजे होंगे। अदालत का कहना था कि कार्यवाही शुरू होने के लिए अधिकतम सीमा 365 दिन है।

आखिरी सवाल कोर्ट ने ईडी से पूछा कि केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया है। आजादी बहुत महत्वपूर्ण है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी प्रश्न गिरफ्तारी के समय को लेकर है कि क्यों चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की गई।

इसके साथ ही अदालत ने इस मैटर की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी।

केजरीवाल-केजरीवाल, यस पापा... सुकेश ने दिल्ली सीएम को लिखा एक और पत्र, पत्नी सुनीता की एक्टिंग को बताया ऑस्कर विनिंग

परिवहन विशेष न्यूज

मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि पिछले कुछ दिनों से जेल में जारी सीएम का नाटक उनके सहयोगियों व सीएम की पत्नी का अभिनय ऑस्कर विजेता रहा। उसने चुटकी लेते हुए लिखा कि जब वह प्ले स्कूल में था तो उस समय की उसे कविता याद आ गई।

पूर्वी दिल्ली। ठगी के मामले में मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि पिछले कुछ दिनों से जेल में जारी सीएम का नाटक, उनके सहयोगियों व सीएम की पत्नी का अभिनय ऑस्कर विजेता रहा।

उसने चुटकी लेते हुए लिखा कि जब वह प्ले स्कूल में था, उस समय की कविता उसे याद आ गई। जिसमें था केजरीवाल-केजरीवाल, हां पापा। चीनी खा रहे हैं, नहीं पापा। झूठ बोलना, नहीं पापा। लोगों को बेवकूफ बनाना, नहीं पापा। डाइट चार्ट का खुलासा, हा, हा, हा।

'लोगों की सहानुभूति लेने को नाटक कर रहे सीएम'

सुकेश ने पत्र में कहा कि तिहाड़ क्लब में सीएम अपने प्रवास के दौरान सभी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। जेल दिल्ली सरकार के पास है। चुनाव के दौरान लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए सीएम नाटक कर रहे हैं।

संजय पर सुकेश ने क्या लिखा

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के लिए लिखा कि वह कह रहे हैं सीएम के साथ जेल में आतंकवादी की तरह बर्ताव किया जा रहा है। जबकि कुछ दिनों पहले तक संजय सिंह खुद तिहाड़ में बंद थे, तब उन्होंने इस तरह की शिकायत नहीं की। इससे यही पता चलता है जेल में उनका अच्छे से ध्यान रखा गया।

यह चीजें जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व पूर्व मंत्री सत्येंद्र के साथ भी हो रही हैं। मेडिकल जमानत हासिल करने और कानून को धोखा देने के लिए सीएम नाटक रच रहे हैं। चार जून को लोग केजरीवाल व उनकी पार्टी को नकार देंगे। यहां तक कहा कि वह सीएम को निराश नहीं करेगा, वह उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनेगा।

देवेन्द्र यादव बने कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद देवेन्द्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के जनरल सेकेट्री और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने आधिकारिक तौर पर आदेश जारी किए।

आदेश के अनुसार देवेन्द्र यादव को तत्काल प्रभाव से दिल्ली स्टेट कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह पंजाब के इंचार्ज की जिम्मेदारी भी संभालते रहेगे।

उल्लेखनीय है कि देवेन्द्र यादव दो बार दिल्ली की बादली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके है।उन्होने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। वो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के भी सदस्य है। बतादें कि अरविंदर सिंह लवली ने इसी शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सबको चौका दिया था। उन्होने कहा था कि दिल्ली कांग्रेस हमेशा से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन के खिलाफ थी।लेकिन पार्टी आलाकमान इस पर आगे बढ गया। मल्लिकार्जुन खडगे को को भेजे चार पेजी चिट्ठी मे लिखा कि आप से गठबंधन और बाहरी शख्स कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी से खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहे है।

उल्लेखनीय है कि अरविंदर सिंह लवली ने 18 अप्रैल, 2017 को भी कांग्रेस पार्टी का हाथ छोडकर भाजपा का फूल थाम लिया था। लेकिन 10 महीने के भीतर ही लवली का भाजपा से मोह भंग हो गया। वह 17 फरवरी,2018 को फिर से कांग्रेस पार्टी में लौट आए थे।

एक ऐसा हत्यारोपी, जिसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऋषिकेश में कराया भंडारा; 27 साल से था फरार

हत्या के मामले में 27 वर्षों से फरार चल रहे आरोपित टिल्लू उर्फ रामदास को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। वित्तीय विवाद में पड़ोस में रहने वाले उसके दो रिश्तेदारों ने अपने घर में बुलाकर किशन लाल की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से रामदास फरार था। पहचान छिपाने के लिए उसने अपना नाम और पता बदल लिया था।

नई दिल्ली। हत्या के मामले में 27 वर्षों से फरार चल रहे आरोपित टिल्लू उर्फ रामदास को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। वित्तीय विवाद में पड़ोस में रहने वाले उसके दो रिश्तेदारों ने अपने घर में बुलाकर किशन लाल की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से रामदास फरार था।

पहचान छिपाने के लिए उसने अपना नाम और पता बदल लिया था। भिखारी का भेष बनाकर वह अलग-अलग धार्मिक स्थानों पर मंदिरों में शरण लेता रहा। क्राइम ब्रांच की टीम को ऋषिकेश में कुछ मंदिरों के पास उसके मोबाइल की लोकेशन मिलने पर पुलिस कर्मियों ने स्वयंसेवक के तौर पर तीन दिनों तक भंडारा का आयोजन किया। रामदास जब भंडारे का प्रसाद लेने पहुंचा तब पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया।

चार फरवरी 1997 को दर्ज हुई शिकायत

डीसीपी के अनुसार, चार फरवरी 1997 को सुनीता नाम की महिला ने ओखला थाने में शिकायत कर बताया कि वह तुगलकाबाद में परिवार के साथ रहती है और मूलरूप से एटा (उत्तर) प्रदेश की रहने वाली है। उसका पति किशन लाल तुगलकाबाद एक्सटेंशन में निजी सफाईकर्मी थे।

पति को घर ले गया आरोपी

तीन फरवरी को ड्यूटी से घर लौटने के बाद पति घर में मौजूद थे। शाम को पड़ोस में रहने वाला पति का रिश्तेदार रामू उनके घर आया था। वह उनके पति को अपने घर ले गया था। रात में जब वह घर नहीं लौटे तब सुबह में वह अपने भाई रामू के घर पहुंची। रामू के घर पर ताला लगा हुआ था।

खिड़की से झांककर देखा तो...

खिड़की से झांककर देखा गया तो घर के अंदर खून फैला हुआ था और चारपाई पर कपड़े में लिपटा हुआ एक शव पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तब शव किशन लाल का पाया गया। महिला ने रामू और उसके बहनोई टिल्लू पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद ओखला थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

उसी वर्ष 15 मई को भगोड़ा घोषित किया

जांच के बाद दोनों को 15 मई 1997 को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। भगोड़ा अपराधियों को पकड़ने के चुनाव आयोग के निर्देश पर क्राइम ब्रांच को कानपुर के रहने वाले रामदास के बारे में जानकारी मिली। वह बार-बार अपना स्थान बदल रहा था और उसका कोई स्थायी पता नहीं था।

संत बनकर मंदिरों में करता भ्रमण

उसके फोन की लोकेशन ज्यादातर हरिद्वार और ऋषिकेश के पास मिली। यह भी पता चला कि वह संत बनकर देश भर में मंदिरों में भ्रमण करता है और धर्मशालाओं में ठहरता है। 2023 में उसका मूवमेंट कन्याकुमारी में होने का पता चला था। ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में चले जाने के कारण उसका पता नहीं लगाया जा सका था।

बेटी के साथ रामदास लेना चाहता था दिल्ली में घर

कई माह तक जांच के बाद हवलदार अमरीश कुमार को रामदास के ऋषिकेश में होने का पता चला। इसके बाद एसीपी रमेश लांबा की टीम ने उसे वहां से दबोच लिया। पूछताछ में रामदास ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी के साथ अपनी बहन के घर दिल्ली आ गया था। उसकी बहन और जीजा नया घर खरीदना चाहते थे, लेकिन उनका किशन लाल के साथ विवाद था।

कानपुर जाकर बदला पता

वित्तीय विवाद पर चर्चा करने के लिए किशन लाल को उसने अपने घर बुलाया था। बातचीत के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि किशन लाल ने उसे और रामू को परिणाम भुगतने की धमकी दी। जिस पर गुस्से में दोनों ने किशन लाल की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद सभी कानपुर चले गए और अपना पता बदल लिया और अपनी पहचान भी बदल ली।

संत बनकर देशभर में घूमा

रामदास ने बदायूं के नाम से आधार कार्ड बनवा लिया था। जांच एजेंसी से बचने के लिए उसने खुद को संत का भेष बनाकर देश भर के धार्मिक स्थलों पर घूमना शुरू कर दिया था। रामदास के पिता कानपुर हथियार फैक्ट्री में काम करते थे। उनका परिवार सरकारी आवास पर रहता था।

सरकारी विभाग से भी बदतर है आपकी कार्यप्रणाली, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा की खिंचाई की

परिवहन विशेष न्यूज

एक मामले में जवाब देने में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा की खिंचाई करते हुए मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर प्रतीत होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कृपया सावधान रहें आपको स्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। अदालत ने कहा कि आपकी व्यवस्था काम नहीं कर रही है लेकिन इसे काम करना होगा।

नई दिल्ली। एक मामले में जवाब देने में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा की खिंचाई करते हुए मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर प्रतीत होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कृपया सावधान रहें, आपको स्थिति के प्रति सचेत रहना होगा।

अदालत ने कहा कि आपकी व्यवस्था काम नहीं कर रही है, लेकिन इसे काम करना होगा। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर मेटा ने अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित नहीं किया तो अदालत इसके विरुद्ध सख्त आदेश पारित कर सकता है।

एक न्यूज चैनल की याचिका पर सुनवाई

अदालत ने उक्त टिप्पणी एक न्यूज चैनल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। न्यूज चैनल ने हार्पर बाजार इंडिया के इंस्टाग्राम पेज को तीसरे पक्ष की शिकायत पर कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत पर ब्लॉक किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

आईटी नियमों का किया जा रहा दुरुपयोग

टीवी टुडे ने अदालत को बताया गया कि आईटी नियमों में कुछ अस्पष्टताओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह भी तर्क दिया कि उन्होंने अपनी शिकायत के साथ मेटा को तीन बार लिखा था और यहां तक कि शिकायत निवारण अधिकारी से भी संपर्क किया था। हालांकि, हर बार यही जवाब मिला कि उन्होंने उचित जगह पर पत्र नहीं लिखा है।

मेटा ने क्या कहा

वहीं, मेटा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता तेजस करिया ने पीठ को सूचित किया कि हार्पर बाजार का इंस्टाग्राम पेज तीन कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद ब्लॉक कर दिया गया था। यह भी कहा कि टीवी टुडे को भेजा गया जवाब कोई निर्णय नहीं है और प्लेटफॉर्म को जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि मेटा को प्रतिदिन बड़ी संख्या में अनुरोध मिलते हैं और आईटी नियमों के तहत एक रिपोर्ट भी दर्ज करता है। हालांकि, पीठ ने कहा कि लाखों उपयोगकर्ता होने के आधार देकर मेटा यह नहीं कह सकता कि वह अपनी कार्यप्रणाली ठीक नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा कि मेटा द्वारा टीवी टुडे को भेजा गया जवाब अंतिम आदेश जैसा है। मुख्य पीठ के रुख को देखते हुए मेटा के अधिवक्ता ने अदालत से एक दिन का समय मांगा। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।

मंडी हाउस इलाके में मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक का विवादित पोस्टर

लोकसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच मंडी हाउस इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक का विवादित पोस्टर लगाया गया। जिसे जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत हटवा दिया मगर यह पोस्टर किसने लगवाएं है इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पोस्टर में यासीन मलिक की रिहाई के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई थी।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच मंडी हाउस इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जेल में बंद जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक का विवादित पोस्टर लगाया गया। जिसे जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत हटवा दिया, मगर यह पोस्टर किसने लगवाएं है इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

पोस्टर में यासीन मलिक की रिहाई के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई थी। बाराखंभा थाने में अज्ञात में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मंडी हाउस सर्कल के पास सफदर हाशमी मार्ग पर लगाए गए पोस्टर में यासीन मलिक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच मुलाकात की फोटो लगाई गई है।

जानकारी के अनुसार, पोस्टर में जो फोटो लगाई गई है वह यूपीए सरकार के समय की है, जब मनोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यासीन मलिक ने उनसे मुलाकात की थी। इसके साथ ही पोस्टर यासीन मलिक की रिहाई के लिए 25 मई को कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई। मालूम हो, दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है।

धोखाधड़ी कर 25 करोड़ रुपये के शेयर हड़पने का आरोप, सगे भाई समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज

कोतवाली सेक्टर-20 में एक व्यक्ति ने अपने भाई और भाभी सहित चार लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके उनकी साझेदारी की कंपनी का करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर को अपने हक में स्थानांतरित (ट्रांसफर) करवा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-20 में एक व्यक्ति ने अपने भाई और भाभी सहित चार लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके उनकी साझेदारी की कंपनी का करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर को अपने हक में स्थानांतरित (ट्रांसफर) करवा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली डिफेंस सर्विस एंकलेव के ललित कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने अपने भाई जेके श्रीवास्तव के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। इस कंपनी में वह और उनकी पत्नी 61.5 प्रतिशत से अधिक के शेयर धारक हैं। पीड़ित का आरोप है कि महेंद्र कुमार दुबली, जेके श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी करके उनकी और उनकी पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनके हिस्से के करीब 25 करोड़ रुपये के शेयर को अपने पक्ष में करवा लिया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसके बड़े भाई और अन्य आरोपितों ने उनको और उनकी पत्नी को कंपनी की देखरेख से जान-बूझकर अलग कर दिया।

दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर चलती रोड स्वीपिंग मशीन में लगी आग, सात-आठ किमी तक लगा लंबा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर सोमवार रात को लगभग नौ बजे नगर निगम की चलती हुई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन में आग लग गई। आग लगने के बाद चालक तुरंत स्वीपिंग मशीन यानी ट्रक से बाहर आ गया जिससे उसकी जान बच गई। हादसा झाड़सा चौक के समीप दिल्ली की तरफ की लेन में हुआ जिसके बाद एक्सप्रेस-वे पर लगभग सात से आठ किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर सोमवार रात को लगभग नौ बजे नगर निगम की चलती हुई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन में आग लग गई। आग लगने के बाद चालक तुरंत स्वीपिंग मशीन यानी ट्रक से बाहर आ गया जिससे उसकी जान बच गई।

हादसा झाड़सा चौक के समीप दिल्ली की तरफ की लेन में हुआ, जिसके बाद एक्सप्रेस-वे पर लगभग सात से आठ किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

आग लगने की सूचना पर सेक्टर 29 दमकल केंद्र से दो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सेक्टर 29 दमकल केंद्र के दमकलकर्मी अर्जुन ने बताया कि रोड स्वीपिंग मशीन में लगी आग को लगभग 40 मिनट में पूरी तरह काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है।

ट्रैफिक पुलिस ने संभाली व्यवस्था

मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन में आग लगने के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर लगे लंबे ट्रैफिक जाम को संभालने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिस पहुंच गई। एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया। इसके कारण एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। वाहन चालक लगभग पौने घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। दमकल कर्मियों द्वारा आग पर पूरी तरह काबू पा लेने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों का आवागमन शुरू करवाया।

नोएडा में आधा दर्जन लोगों ने युवक के साथ की मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

नोएडा में छह लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की बहन ने पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई है। युवती का आरोप है कि वह शिकायत को लेकर थाने और चौकी की चक्कर लगाती रही लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

नोएडा। कोतवाली फेज-तीन में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आधा दर्जन लोगों ने उसके भाई के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मूलरूप से बिहार की रानी कुमारी ने दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि के भाई राहुल के साथ अमित चौहान, अमित का साला, ओला चालक मोंटू और पांच अन्य लोगों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

आरोपितों ने किया जानलेवा हमला

पीड़िता का कहना है कि उसके भाई के साथ 19 अप्रैल को मारपीट हुई। उसके भाई के ऊपर आरोपितों ने जानलेवा हमला किया। उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद नहीं की।

युवती के अनुसार वह थाने और चौकी की चक्कर लगाती रही, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता के अनुसार उसने जब पुलिस उपायुक्त सुनीति से मुलाकात की तथा अपनी शिकायत दर्ज करने की मांग की तो उनके आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

नौ श्रमिकों को लेकर जा रहे ई-रिक्शा को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत; आठ घायल

राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र के धनवापुर चौक के पास सोमवार शाम छह बजे उल्टी दिशा से जा रहे एक ई-रिक्शा को सामने से कीआ कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार एक श्रमिक की मौत हो गई। चालक समेत आठ लोग घायल हैं। सभी को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनमें चार लोग गंभीर बताए जा रहे हैं।

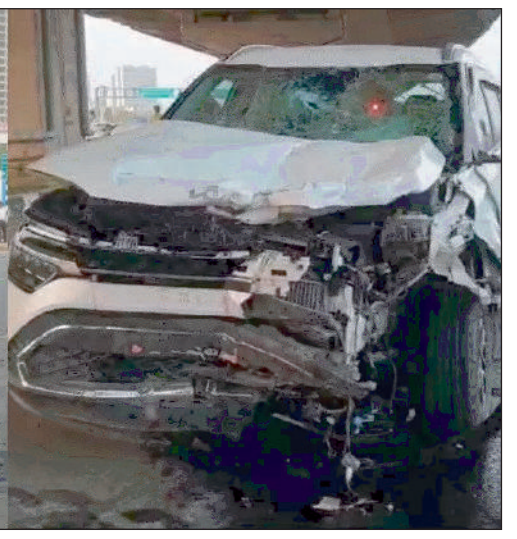

गुरुग्राम। राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र के धनवापुर चौक के पास सोमवार शाम छह बजे उल्टी दिशा से जा रहे एक ई-रिक्शा को सामने से कीआ कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार एक श्रमिक की मौत हो गई। चालक समेत आठ लोग घायल हैं। सभी को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें चार लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर ई-रिक्शा चालक राजेंद्र पार्क के गली नंबर-5 निवासी पंकज अपने ई-रिक्शा में आठ श्रमिकों को बिठाकर धनवापुर से राजेंद्रा पार्क जा रहा था। उल्टी दिशा में चलने के दौरान द्वारका एक्सप्रेस-वे (Dwarka Expressway) के नीचे धनवापुर चौक के पास सामने से आई कीआ कार से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिक्शा कई पलटियां खाते हुए दूर जा गिरा। चालक और सवारियां भी सड़क पर दूर जा गिरीं। चालक समेत ई-रिक्शा में सवार आठों लोगों को नागरिक अस्पताल ले जाया गया। यहां एक सवार ने दम तोड़ दिया। उनकी पहचान 20 वर्षीय श्रमिक रवि के रूप में की गई है। वह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और यहां भीमगढ़ खेड़ी में रहते थे। वहीं कीआ कार में पांच लोग सवार थे। हादसे में उन्हें कोई चोटें नहीं आईं। राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। घायलों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

गहराते जल-संकट से जीवन एवं कृषि खतरे में

ललित गर्ग

भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31 प्रतिशत है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है।

> “ पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है? जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

मानवीय गतिविधियों और क्रिया-कलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के साथ जलाशयों एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को गंभीर जल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते इसी जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस से पैंतीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। जो सूखे जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है। जिसके मूल में अल नीनो घटनाक्रम का प्रभाव एवं वर्षा की कमी को बताया जा रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज भारत गंभीर जल-संकट के साए में खड़ा है। अनियोजित औद्योगीकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान एवं ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, वर्षा की कमी, पर्यावरण विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता भारत को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा रही है।

भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31 प्रतिशत है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है। स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी चिंताजनक है, पश्चिम में 34 प्रतिशत और उत्तर में 32.5 प्रतिशत जलाशय क्षमता है। हालाँकि, पूर्वी और मध्य भारत की स्थिति बेहतर हैं, उनके पास अपने जलाशयों की सक्रिय क्षमता का क्रमशः 40.6 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है, पिछले वर्ष वर्षा कम थी, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, 2023 का मानसून असमान था क्योंकि यह अल नीनो वर्ष भी था- एक जलवायु पैटर्न जो आम तौर पर इस क्षेत्र में गर्म और शुष्क परिस्थितियों का कारण बनता है। इससे काफी चिंता पैदा हुई है। वर्तमान में, सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, और देश भर में पीने के पानी की उपलब्धता और जलविद्युत उत्पादन पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। भविष्य को देखते हुए, आने वाले महीनों में और अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है, जो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बड़ा जल संकट उभरने वाला है।

लंबे समय तक पर्याप्त बारिश न होने के कारण जल भंडारण में यह कमी आई है। जिसके चलते कई क्षेत्रों में सूखे जैसे और असुरक्षित हालात पैदा हो गये हैं। जिससे विभिन्न फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश की आधी कृषि योग्य भूमि आज भी मानसूनी बारिश के निर्भर है। ऐसे में सामान्य मानसून की स्थिति पर कृषि का भविष्य पूरी तरह निर्भर करता है। वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी आसन्न संकट से निपटने के लिये जल संरक्षण के प्रयास घरों से लेकर तमाम कृषि पद्धतियों और औद्योगिक कार्यों तक में तेज करने की जरूरत है। जल भंडारण और वितरण दक्षता में सुधार के लिये पानी के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन प्रणालियों में बड़े निवेश की तात्कालिक जरूरत भी है। इसके साथ ही जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही आम लोगों को प्रकृति के इस बहुमूल्य संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा हेतु प्रेरित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाने की जरूरत है।

पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है? जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पानी धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधारभूत आवश्यकता है। आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बना दिया है। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन चार प्रतिशत जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है। भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये है, उन्हीं प्रयत्नों को व्यापक स्तर पर अपनाने एवं जल-संरक्षण क्रांति को घटित करने की अपेक्षा है।

सदियों से निर्मल जल का स्त्रोत बनी रहीं नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, अब उन पर जलवायु परिवर्तन का घातक प्रभाव पड़ने लगा है। जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है, और भू-जल स्तर लगातार घट रहा है। धरती पर सुरक्षित और पीने के पानी के बहुत कम प्रतिशत के आंकलन के द्वारा जल संरक्षण या जल बचाओ अभियान हम सभी के लिये बहुत जरूरी हो चुका है। जल को बचाने में अधिक कार्यक्षमता लाने के लिये सभी औद्योगिक बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स, स्कूल, अस्पतालों आदि में बिल्डरों के द्वारा उचित जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिये। देश के सात राज्यों के 8220 ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधनों के लिए अटल भूजल योजना चल रही है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही, नल से जल, नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने जैसे प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हमारे यहां जल बचाने के मुख्य साधन हैं नदी, ताल एवं कूप। इन्हें अपनाओं, इनकी रक्षा करो, इन्हें अभय दो, इन्हें मरुस्थल के हवाले न करो। गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाकर या उनका जीर्णोद्धार करके बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। धरती के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं।

पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। जल का संकट एवं विकट स्थितियां अति प्राचीन समय से बनी हुई है। इसी कारण राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि प्रांतों में जल संरक्षण के लिये नाड़ी, तालाब, जोहड़, बन्धा, सागर, समंद एवं सरोवर आदि बनाने की प्राचीन परम्परा रही है। जहाँ प्रकृति एवं संस्कृति परस्पर एक दूसरे से समायोजित रही हैं। राजस्थान के किले तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं पर इनका जल प्रबन्धन विशेष रूप से देखने योग्य है और अनुकरणीय भी हैं। जल संचयन की परम्परा वहाँ के सामाजिक ढाँचे से जुड़ी हुई हैं तथा जल के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण के कारण ही प्राकृतिक जलस्रोतों को पूजा जाता है।

इलेक्ट्रिक कार माइलेज: दावा हकीकत से काफी दूर, खरीदने जा रहे हैं तो पहले कर लें पूरी पड़ताल

कार कंपनियां इस बात की जानकारी अपने इश्तेहार में नहीं देती हैं। अलबत्ता वह क्लेम्ड माइलेज या रेंज के आगे स्टार जरूर लगा देती हैं ताकि उनके दावे को चुनौती नहीं दी जा सके। जानकारी के अभाव में ई-कार मालिक इस उम्मीद से 300 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ता है क्योंकि कार कंपनी ने एक बार चार्ज करने पर कार के 300 किलोमीटर तक चलने का दावा किया है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे हैं तो इसकी पूरी पड़ताल कर लें कि उसका वास्तविक माइलेज क्या है। सच्चाई यह है कि उनका टेस्ट रेंज का जो दावा होता है, भारतीय सड़क और परिस्थिति के अनुसार सामान्य स्थिति में माइलेज 60-65 फीसद हो होता है।

कार की माइलेज या क्लेम्ड रेंज (Electric Car Range) तय करने के लिए गाड़ी की टेस्टिंग अधिकतम 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से बिना एयरकंडीशन चलाए 25 डिग्री तापमान पर एक समान सड़क पर की जाती है। ऐसे में, अगर आप ई-कार चलाते समय 50 किलोमीटर से अधिक स्पीड रखेंगे, एसी चलाएंगे या फिर अपने अलावा कई अन्य लोगों को कार में बिठाएंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी और कार वह माइलेज नहीं देगी जिसका दावा किया गया है। यहां तक की ट्रैफिक अधिक है या सड़कें टूटी-फूटी हैं तो भी माइलेज का दावा फेल हो सकता है। मौसम में फर्क की वजह से राजस्थान में वह रेंज नहीं मिलेगी जो मुंबई में मिलेगी।

कार कंपनियां विज्ञापनों में नहीं बताती पूरी बात

कार कंपनियां इस बात की जानकारी अपने इश्तेहार में नहीं देती हैं। अलबत्ता वह क्लेम्ड माइलेज या रेंज के आगे स्टार जरूर लगा देती हैं ताकि उनके दावे को चुनौती नहीं दी जा सके। जानकारी के अभाव में ई-कार मालिक इस उम्मीद से 300 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ता है क्योंकि कार कंपनी ने एक बार चार्ज करने पर कार के 300 किलोमीटर तक चलने का दावा किया है। लेकिन 300 किलोमीटर से काफी पहले कार की बैट्री खत्म हो जाती है और और उन्हें अपनी गाड़ी को चार्जिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए अन्य वाहन बुलाना पड़ता है।

इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों में विश्वास की कमी

घरेलू ई-कार बाजार में 74 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ प्रोजक्ट ऑफिसर आनंद कुलकर्णी कहते हैं, "भारत में मोडिफायड इंडिया ड्राइव साइकल (एमआईडीसी) के आधार पर गाड़ी की रेंज तय होती है। ऐसे में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाने पर रेंज में कमी आएगी ही। हमारे डीलर बिक्री के दौरान ग्राहकों को रेंज संबंधित पूरी जानकारी देते हैं और यह बताते हैं कि इस इलाके में इतनी रेंज मिल सकती है, फिर भी ग्राहक अपने हिसाब से चलाता है तो रेंज वैरी कर सकती है। पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों में भी क्लेम्ड रेंज में अंतर आता है। ई-कार सिर्फ चार साल पहले बाजार में आई है और चार्जिंग स्टेशन भी कम हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि हम फंस जाएंगे।"

उन्होंने बताया कि इस साल अप्रैल से 90 किलोमीटर तक की अधिकतम स्पीड से गाड़ी की रेंज तय करने की कवायद शुरू हो गई है। टाटा कंपनी के अनुसार उनका क्लेम्ड रेंज 460 है लेकिन जब ग्राहक आते हैं तो वह 300-320 किलोमीटर माइलेज ही बताते हैं।

बैट्री पुरानी होने पर भी रेंज में आएगा फर्क

सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने बताया कि इलेक्ट्रिक कार की रेंज हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है। बैट्री पुरानी होती है तो उसकी क्षमता कम होती जाती है। नई बैट्री के इलेक्ट्रॉल व अन्य केमिकल ताजा होते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों को रेंज की आदर्श स्थिति और व्यावहारिक स्थिति के बारे में लिखना चाहिए। लेकिन प्रतिस्पर्धा की वजह से कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं।

क्लेम्ड रेंज और असली रेंज पर भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि ग्राहकों को दिक्कत आ रही है तो वह उपभोक्ता मामले मंत्रालय के ग्राहक प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत कर सकते हैं। गत वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 40 लाख यात्री कार की बिक्री हुई जबकि इलेक्ट्रिक कार की संख्या सिर्फ 90,432 थी। इलेक्ट्रिक कार में बड़ी हिस्सेदारी कैब की है और ये कार मुख्य रूप से एक शहर के भीतर की ही चलती हैं।

आ गया सिंगल चार्ज में 136 किमी रेंज देने वाला स्कूटर, 1.10 लाख रुपये से शुरू है कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

इसकी कीमत 1.10 लाख रुपये एक्सशोरूम निर्धारित की गई है। 9999 रुपये देकर इसे बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी मई में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं इसका ST ट्रिम वेरिएंट 119900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसमें 7 इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। जिसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक ने भारतीय मार्केट में Ampere Nexus नाम से एक स्कूटर लॉन्च किया है। नेक्सस को दो वेरिएंट EX और ST में पेश किया गया है। यहां इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स और टॉप स्पीड के बारे में बताने वाले हैं।

कीमत और बुकिंग

इसकी कीमत 1.10 लाख रुपये एक्सशोरूम निर्धारित की गई है। 9,999 रुपये देकर इसे बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी मई में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, इसका ST ट्रिम वेरिएंट 1,19,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसमें 7 इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। जिसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है।

टॉप स्पीड, रेंज और बैटरी

Nexus इलेक्ट्रिक स्कूटर चार कलर ऑप्शन जांस्कर एक्वा, स्टील ग्रे, इंडियन रेड और लूनार वाइट में लॉन्च किया गया है। स्कूटर में 4kW मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 93 किमी/प्रतिघंटा है। इसे सिटी मोड में 63kmph और ईको मोड में 42kmph चलाया जा सकता है। सिंगल चार्ज में ये 136 किमी तक चल सकता है।

डिजाइन

स्कूटर आकर्षक डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें आई कैचिंग हेडलाइट सेटअप, स्लीक DRls दिए गए हैं। नए लॉन्च किए गए ई-स्कूटर में ट्विन सस्पेंशन के साथ बेस्ट-इन-क्लास हाइब्रिड स्विंग आर्म दिया गया है। IP67 की रेटिंग भी इसे मिली हुई है। Ampere Nexus में फ्रंट में टेलिस्कॉपिक फॉर्क और रियर में शॉक ऑब्जर्बर दिए गए हैं। यह 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ लाया गया है।

मारुति और टोयोटा को चुनौती देने हुंडई कर रही हाइब्रिड कार की तैयारी, जानें कब तक होगी पेश

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai भारतीय बाजार में कई बेहतरीन वाहनों को ऑफर करती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अब Hybrid Cars को लाने की तैयारी कर रही है। हुंडई की ओर से कब तक हाइब्रिड तकनीक वाली कारों को पेश किया जा सकता है। किन कारों में सबसे पहले इस तकनीक को दिया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल साउथ कोरियाई कंपनी Hyundai की ओर से जल्द ही Hybrid तकनीक वाली कारों को लाने की तैयारी की जा रही है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि मारुति और टोयोटा को कड़ी चुनौती देने के लिए हुंडई की ओर से कब तक हाइब्रिड तकनीक वाली कारों को पेश किया जा सकता है।

Hyundai लाएगी Hybrid Cars

हुंडई की ओर से भी हाइब्रिड तकनीक वाली कारों को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष यूइसुन चुंग ने भारतीय कर्मचारियों से कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही हाइब्रिड तकनीक वाली कारें भी पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा होंगी।

दुनियाभर में बढ़ रही मांग

भारत के साथ ही दुनियाभर के कई देशों में हाइब्रिड तकनीक वाली कारों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए हुंडई भी इलेक्ट्रिक कारों के साथ ही अपने पोर्टफोलियो में हाइब्रिड तकनीक वाली कारों को लाने के प्रति गंभीर है। यह योजना कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की योजना से अलग है।

वित्त वर्ष 2023 में रही हाइब्रिड वाहनों की मांग

बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में भी हाइब्रिड तकनीक वाले वाहनों की मांग में बढ़ोतरी हुई। देशभर में करीब 85 से 90 हजार के आस-पास इस तकनीक वाली कारों की बिक्री हुई। जो कुल बिक्री का दो फीसदी है। वहीं कुछ और कारों को इस साल में लाने की तैयारी की जा रही है।

किसे मिलेगी चुनौती

भारतीय बाजार में फिलहाल मारुति और टोयोटा (Toyota Cars) की ओर से हाइब्रिड तकनीक वाले वाहनों की बिक्री की जाती है। दोनों कंपनियां अपने पोर्टफोलियो की कई कारों को इस साल भी हाइब्रिड तकनीक के साथ लाने की तैयारी कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक मारुति (Maruti Suzuki) की ओर से हाइब्रिड तकनीक वाली कारों के लिए 2031 तक 7.5 लाख यूनिट्स की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में हुंडई की ओर से भी अगर इस तकनीक वाली कारों को लाया जाता है तो सीधे तौर पर मारुति और टोयोटा को चुनौती मिलेगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई मोटर ग्रुप की ओर से पहली हाइब्रिड कार को साल 2026 तक पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से हाइब्रिड तकनीक पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और हुंडई के साथ किआ भी हाइब्रिड स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन को लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक क्रेटा, अल्काजार, वरना और टक्सन जैसे वाहनों को 2026-27 तक हाइब्रिड तकनीक के साथ भारत में (Hybrid Cars in India) लाया जा सकता है। इससे पहले कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर 2025 तक क्रेटा को पेश किया

दमदार इंजन के साथ लॉन्च हुई डुकाटी डिजर्ट एक्स रैली बाइक, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

लग्जरी बाइक निर्माता Ducati की ओर से भारत में बेहद दमदार बाइक्स को बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से हाल में ही एडवेंचर बाइक के तौर पर DesertX Rally बाइक को लॉन्च किया गया है। इस बाइक को किन खूबियों के साथ लाया गया है। इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में लग्जरी बाइक्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अक्सर एडवेंचर के शौकीन लोग दमदार इंजन और फीचर्स वाली बाइक्स के साथ लंबे सफर पर निकलते हैं। इसी को देखते हुए Ducati की ओर से DesertX Rally बाइक को इंडिया में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने किस कीमत पर और किन फीचर्स के साथ इसे लॉन्च किया है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

लॉन्च हुई Ducati DesertX Rally बाइक

डुकाटी की ओर से भारतीय बाजार में एक और दमदार बाइक को लॉन्च किया गया है। कंपनी की ओर से DesertX Rally बाइक को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च से पहले कंपनी ने अप्रैल महीने में ही इसके लिए बुकिंग को शुरू किया था।

कैसे हैं फीचर्स

Ducati DesertX Rally बाइक को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो लंबे सफर पर जाने के साथ ही हर तरह की सड़क पर बाइक को चलाने का अनुभव करना चाहते हैं। इस बाइक में हाई फ्रंट मडगार्ड के साथ स्प्लिट ब्रेक लाइन, स्पोक्ड रिम्स, केवाईबी शॉक अर्ब्जाबर, 280 एमएम की ग्राउंड क्लियरेंस, चार पावर मोड्स और तीन पावर लेवल, क्रूज कंट्रोल, फुल एलईडी लाइट्स, पांच इंच कलर्ड टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, विली कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंडयूरो और रैली मोड्स, कार्नरिंग एबीएस, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स को दिया गया है।

कितना दमदार इंजन

Ducati DesertX Rally बाइक में कंपनी की ओर से 937 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन दिया गया है। जिससे इसे 110 हॉर्स पावर और 92 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाइक में 21 लीटर के पेट्रोल टैंक को दिया गया है। बाइक की सर्विस 24 महीने या 15 हजार किलोमीटर पर होगी और हर 30 हजार किलोमीटर पर इसके वॉल्व को चेक करवाना होगा।

कितनी है कीमत

डुकाटी ने अपनी नई बाइक को 23.70 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इस बाइक के लिए पहले से ही बुकिंग जारी हैं। लेकिन चार मई के बाद इसे कुछ चुनिंदा डीलरशिप पर डिस्प्ले किया जाएगा। बाइक की डिलीवरी भी मई के आखिर तक शुरू की जाएगी।

'पुनर्वितरण' की कवायद और चुनावी पारा

डा. अश्विनी महाजन
कालेज एसोशिएट प्रोफेसर

भारत में चुनावी माहौल हर दिन गर्म होता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, जिसे वह संकल्प पत्र कहती है, में साफ कहा है कि वह समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगी।

हैदराबाद में एक रैली में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संकेत दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी जाति सर्वेक्षण के वादे के बाद देश की संपत्ति, नौकरियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का आर्थिक रूप से पुनर्निर्धारण करेगी। उन्होंने कथित तौर पर कहा, 'हम एक जाति जनगणना करेंगे ताकि पिछड़े, एससी, एसटी, सामान्य जाति के गरीबों और अल्पसंख्यकों को पता चले कि देश में उनकी (संख्या के संदर्भ में) कितनी हिस्सेदारी है। इसके बाद, यह पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण किया जाएगा कि देश की संपत्ति किसके पास है। हम आपको वह देंगे जो आपका अधिकार है।' हालांकि पुनर्वितरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट है : 'जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या, उसको उतने ज्यादा अधिकार।' कैसे? पार्टी की मंशा कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट हो जाती है : पहला, विभिन्न जातियों और अल्पसंख्यकों के आकार का अनुमान लगाया जाएगा। दूसरा, वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण से पता चलेगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है'

भारत में चुनावी माहौल हर दिन गर्म होता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, जिसे वह संकल्प पत्र कहती है, में साफ कहा है कि वह समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगी। पार्टी का मुख्य फोकस भारत के युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों पर है। जब कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि देश को जाति के नाम पर बांटना 'पाप' है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए चार सबसे बड़ी जातियां युवा, महिलाएं, गरीब और किसान हैं और उनकी पार्टी उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी। पीएम के रूप में मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जाति और धर्म के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। इस बीच, सरकार ने गरीबों को घरों के लिए सब्सिडी, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीबों के लिए शौचालय, बिजली, पानी की सुविधा या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदान किया। सभी को सरकारी सहायता उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रदान की जाती थी, न कि जाति या धर्म के आधार पर। लेकिन जाति जनगणना का बार-बार जिक्र करने से इस बात की बू आती है कि ये राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं।

कांग्रेस के वादे

हैदराबाद में एक रैली में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संकेत दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी जाति सर्वेक्षण के वादे के बाद देश की संपत्ति, नौकरियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का आर्थिक रूप से पुनर्निर्धारण करेगी। उन्होंने कथित तौर पर कहा, 'हम एक जाति जनगणना करेंगे ताकि पिछड़े, एससी, एसटी, सामान्य जाति के गरीबों और अल्पसंख्यकों को पता चले कि देश में उनकी (संख्या के संदर्भ में) कितनी हिस्सेदारी है। इसके बाद, यह पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण किया जाएगा कि देश की संपत्ति किसके पास है। हम आपको वह देंगे जो आपका अधिकार है।' हालांकि पुनर्वितरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट है : 'जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या, उसको उतने ज्यादा अधिकार।' कैसे? पार्टी की मंशा चार बिंदुओं पर स्पष्ट हो जाती है : पहला, विभिन्न जातियों और अल्पसंख्यकों के आकार का अनुमान लगाया जाएगा। दूसरा, वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण से पता चलेगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। तीसरा, वे क्रांतिकारी कार्य करेंगे और सभी को उनका अधिकार दिलाएंगे। चौथा, इस बारे में भी स्पष्टता है कि किसे कितना मिलेगा- 'जितनी आबादी उतना हक।' यानी जनसंख्या के अनुपात में अधिकार। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2006 में कुछ ऐसा ही कहा था। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ पूर्व पीएम का बचाव करते हुए तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, जो उन्होंने कहा हमें उसकी गहराई में जाना चाहिए।

उन्होंने कहा था, 'मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं : कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, और सामान्य बुनियादी ढांचे की आवश्यक सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ-साथ एससी/एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक और महिलाएं व बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए।' हालांकि, सिंह ने एससी और एसटी के उत्थान के लिए बनाई गई नीतियों के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का अलग से जिक्र किया। उस समय के समाचार पत्रों में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। चूंकि यह एक लिखित भाषण था, इसलिए जुबान फिसलने का कोई बहाना नहीं हो सकता। यह राहुल गांधी या मनमोहन सिंह के बारे में नहीं है बल्कि विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों से लुभावने वादे करके वोट हासिल करने के बारे में है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार देश के हर वर्ग के साथ समान व्यवहार करेगी। लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने की होड़ में राजनीतिक दल समाज और संविधान के प्रति अपना कत्र्तव्य भूल जाते हैं।

मोदी ने क्या कहा?

कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जाति जनगणना के बाद वे देश में धन और नौकरियों का आकलन करने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण करेंगे जिसके बाद वह 'क्रांतिकारी' कदम उठाएगी और सभी को उनका अधिकार देगी, जो उनकी आबादी के अनुसार होगा। पीएम मोदी 2006 के मनमोहन सिंह का हवाला दे रहे थे और कांग्रेस के न्याय पत्र को समझा रहे थे। उनके अनुसार, कांग्रेस मुसलमानों, अधिक बच्चों वाले लोगों, घुसपैठियों को पैसे बांटेगी। भारतीय मुस्लिम आबादी 1951 में 9.9 प्रतिशत से बढक़र 2011 में 14.2 प्रतिशत हो गई। यह समझ से परे है कि राजनीतिक टिप्पणीकार, जो अपने बयान के लिए पीएम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में आने पर कांग्रेस के 'क्रांतिकारी' वादे पर चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। दोषी वे लोग हैं जो राजनीतिक लाभ कमाने के लिए जाति/धर्म को वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखते हैं। अब यह जनता के हाथ में होगा कि वह किसे सत्ता सौंपना चाहती है। इसके लिए हमें चार जून का इंतजार करना होगा, जब जनादेश सामने होगा।

संपादक की कलम से

न भाजपा गोरी, न कांग्रेस काली

यहां बिका कौन बगावत किसकी, लुट रहा चुनाव ये शरारत किसकी। हिमाचल में दोनों प्रमुख पार्टियों के ताजा आचरण के बीच प्रदेश का चरित्र गौशाला हो गया या आवारा पशुओं की तरह लावारिस दिखाई दे रहा है। गाय की गिनती उसके दूध की मिकदार से है और जैसे ही वह दुधारू नहीं रहती, खुले में आवारा छोड़ दी जाती। कमोबेश समाज के इसी सिद्धांत पर राजनीति ने भी खुद की दिशा तय कर ली है यानी पार्टियां अब नेताओं के साथ दुधारू गाय जैसा व्यवहार कर रही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि नेता खुद को गाय नहीं मानता और न ही यह अधिकार पार्टियों को देता है कि उसकी नस्ल पर प्रतिकूल टिप्पणी हो, हालांकि जब से कांग्रेस से अलहदा होकर छह विधायक पूर्व हो गए, उनकी जमात व जमीर पर कई टिप्पणियां हुई हैं। उन्हें बदनाम करने की नस्ली टिप्पणियां कांग्रेस के हुकम और हुकमरानों के इरादों से निकलीं, लेकिन पार्टी के दो टिकटों ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति एक जैसी मिट्टी पर ही उग रही है। कैप्टन रंजीत राणा भाजपा की ओर से कांग्रेस के राजिंद्र राणा से लड़े, यह बस एक कहावत बन गई, जबकि अब भी ये दोनों चेहरे आमने-सामने हैं, बस पार्टियों की जुबान फिसल गई। यह बनाम-बनाम-बनाम याद रखें या कब्र से जुबान खोजें जो मुकाबिल हो। राकेश कालिया आज फिर कांग्रेस में आ गए, तो अतीत के फाहों में किसका दर्द रहा। वर्तमान चुनावों में यह तो साबित हो ही गया कि सियासत मौकापरस्ती का सबसे बड़ा मक्का है और यहां बयानों के झूठ आम मतदाता के दिमाग में सुराख कर सकते हैं।

कौन किसके करीब, कौन किसके विरोध में खड़ा, यह फरेब की जटाओं में जूएं ढूंढने का काम है। कम से कम चुनावों में यह तो पता चल गया कि लोकतंत्र के वाहक अब ढूंढे नहीं मिल रहे। कांग्रेस के छह बागी शामिल करके भाजपा ने साबित कर दिया कि सत्ता पक्ष की आंधियों के पीछे पतवार नहीं है। लगभग एक महीने से भाजपा की उम्मीदें अपनी पतवार थामे जनता को खबर दे चुकी हैं कि चुनावों में उसकी मर्जी क्या है, जबकि कांग्रेस के युद्धनाद में बागियों के प्रति गुस्सा, आरोपों का बारूद और अपने भीतर नेता बनाने की खोज थी। कुछ मिल गए, कुछ बाकी हैं। कुछ भाजपा से आ गए, कुछ की फाइल बाद में आती रहेगी। हाथ बंधे चुनाव में जी हुजूरी यह कि कुछ नेताओं को मनाया जा रहा है कि आइए इस सावन में हरियाली के लिए उतर जाइए। चुनावों ने नेता फस्ट कर दिया, इसलिए यही एक क्षेत्र है जहां कोई रंगभेद नहीं। न भाजपा गोरी, न कांग्रेस काली, सिर्फ चूर्ण चटाने की देरी है। भाजपा ने छह बागियों और तीन निर्दलीयों को चटा कर साबित कर दिया कि उसका फार्मूला चुनावी हाजमे के लिए कितना मुफीद है। कांग्रेस को अपने ही चूर्ण पर संदेह है कि यह हजम होगा भी कि नहीं। डा. रामलाल मार्कंडेय अपनी जुबान पर कांग्रेस के चूर्ण से यह तय नहीं कर पा रहे कि इसका असर मीठा होगा या कड़वा और कहीं गंगू राम मुसाफिर को इस वक्त चूर्ण की सख्त जरूरत है, तो कांग्रेस कंजूस क्यों रही। जो भी हो कांग्रेस के टिकटों का आबंटन फिलहाल आवारा के बीच से दुधारू गाय खोजने जैसा प्रतीत हो रहा है। चुनाव के वर्तमान अध्याय वे नहीं जिन्हें पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है, बल्कि वे हैं जिन्हें फाड़ा जा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच अदला बदली को अगर मतदाता भविष्य मान रहा है, तो कल की तस्वीर में कौन नेता चौराहे और कौन खाई के नजदीक होगा, कहा नहीं जा सकता। इतना तो मतदाता भी जानता है कि उसे कूड़े में से ही उपयोगिता ढूंढनी है, तो सर्वप्रथम ऐसे सिक्के देखेगा जो कभी न कभी चले तो थे।

राय

अब आरक्षण पर चुनाव!

अब विकास, भारत सरकार की प्रमुख उपलब्धियां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और उसके प्रधानमंत्री की विराट, वैश्विक हैसियत और तीसरे स्थान की आर्थिक महाशक्ति बनने सरीखे मुद्दे तो नेपथ्य में चले गए हैं अथवा प्रसंगवश बन गए हैं, लेकिन आरक्षण एक राष्ट्रीय, केंद्रीय मुद्दा बन गया है। चूंकि आरक्षण सीधा संविधान और दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा ग्रामीण स्तर पर भी लोग चिंता जताने लगे हैं कि क्या देश का संविधान बदल दिया जाएगा? तो फिर आरक्षण भी समाप्त किया जा सकता है? यह कांग्रेस और सहयोगी दलों की पहली चुनावी सफलता लगती है कि फिलहाल संविधान और आरक्षण राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं। गली-गली, मुहल्ला-दर-मुहल्ला इनकी ही चर्चा है। लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर आशंकित हैं। अभी यह तय नहीं है कि इनसे ध्रुवीकरण होगा, तो कितना होगा? लेकिन भाजपा देश के कटघरे में है, क्योंकि उसे ही जनता को पूरी तरह आश्वस्त करना है कि संविधान किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा और आरक्षण लागू है तथा जारी रहेगा। बल्कि उसका दुरुपयोग बंद कराया जाएगा। दरअसल बहस भाजपा सांसदों-अनंत हेगड़े और लल्लू सिंह-के बयानों से ही शुरू हुई कि 400 पार के नारे और लक्ष्य के मकसद क्या हैं? उसी के आधार पर कांग्रेस ने आरोप चस्पा करने शुरू किए कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा-संघ 400 सीटों का जनादेश इसलिए मांग रहे हैं, ताकि संसद में पर्याप्त बहुमत के जरिए संविधान बदला जा सके और आरक्षण भी समाप्त किया जा सके।

राहुल गांधी तो कहते रहे हैं कि भाजपा-संघ की बुनियादी सोच आरक्षण-विरोधी है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रचारक नेताओं के आरोप हैं कि पिछड़ों के आरक्षण की आड़ में कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को 'पिछड़ा' घोषित कर उन्हें आरक्षण दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बाबा अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को जिस तरह 4 फीसदी आरक्षण दिया गया है, वह असंवैधानिक है। हम चुनाव के बाद इस मामले को देखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह सर्वोच्च अदालत का भी फैसला है। कांग्रेस की वजह से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष इसका जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बेल्लारी में याद दिलाया कि जम्मू-कश्मीर में कभी भी आरक्षण लागू नहीं हो पाया था। भाजपा-एनडीए की सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। उसके बाद ही भाजपा ने वहां आरक्षण लागू किया है। इस राजनीतिक बहस का जनता के मानस पर काफी असर पड़ेगा। इसका फलितार्थ यह भी हो सकता है कि जिन राज्यों में भाजपा ने 100 फीसदी सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था, वहां यह सफलता मिलने के आसार कम होते जा रहे हैं। राजस्थान और उप्र इनके उदाहरण बताए जा रहे हैं। सत्ता-पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह मात्र दो ही मुख्य प्रचारक हैं, जो जनता को आश्वस्त करने में जुटे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को कुछ नहीं होने वाला है। उनके अलावा, आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने भी सफाई दी है कि संघ ने हमेशा संविधान सम्मत आरक्षण का समर्थन किया है। जब तक संवैधानिक तौर पर आरक्षण अनिवार्य लगे, तब तक यह जारी रहना चाहिए। राहुल गांधी को संघ प्रमुख के बयान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान 2015 में संघ प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। उस बयान के बाद भाजपा के लिए चुनाव पर पानी फिर गया था।

जलवायु परिवर्तन और भारतीय चुनाव

संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व मौसम विज्ञान संस्था ने एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक रिपोर्ट गत सप्ताह जारी की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव एशिया में विश्व औसत से ज्यादा पड़ रहा है। इस क्षेत्र में कई देशों में आज तक का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है जिसके कारण इस महाद्वीप में 2023 में 90 लाख लोग बाढ़ों और तूफानों से प्रभावित हुए। दो हजार लोग काल का ग्रास बन गए। जलवायु परिवर्तन ने बाढ़, सूखे और तूफानों की घटनाओं को न केवल बढ़ाया है, बल्कि उनकी भयानकता को भी बढ़ाया है, जिसका दुष्प्रभाव वहां के समाजों, अर्थ व्यवस्थाओं और मानव जीवन पर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य सूचकों जैसे कि जमीनी तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के जलस्तर के बढऩे से बिगड़ती हुई स्थिति का पता चल रहा है। 1960-1990 के दौर के मुकाबले तापमान वृद्धि की दर लगभग दुगनी हो गई है। 2023 में जहां एक ओर सूखा पड़ा, वहीं दूसरी ओर भयानक बाढ़ें आईं। चीन की बाढ़ों और भारत में सूखे से 65 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। चीन में 140 वर्षों का वर्षा का रिकार्ड टूट गया। वहीं दक्षिण पश्चिमी चीन भारी सूखे की चपेट में रहा। भारत में लू के कारण 100 लोगों की मौत हो गई और सिक्किम का तीस्ता-3 बांध बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया, जिस दुर्घटना में 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बढ़ते तापमान के कारण इस तरह की घटनाओं के बढऩे की संभावना है।

भारत और बांग्लादेश में लू की संभावनाओं में 30 गुणा वृद्धि की आशंका पैदा हो गई। एशिया के तेज गति से बढ़ते तापमान के चलते इसके ग्लेशियर भी खतरे में पड़ गए हैं। मुख्य 22 ग्लेशियरों में से 20 में भारी नकारात्मक बदलाव हुए पाए गए हैं, यानी ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हुई है। तापमान वृद्धि से समुद्र का जल भी ज्यादा गर्म हो रहा है जिसके कारण भारी बारिश और समुद्री तूफानों का खतरा बढ़ा है। पिछले चार दशकों में अरब सागर में समुद्री तूफानों की संख्या में डेढ़ गुणा वृद्धि हुई है और तूफानों की घातकता भी बढ़ी है। जुलाई और अगस्त 2023 में हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण हुई भारी तबाही का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है जिसको भारत सरकार ने आपात स्थिति घोषित किया। इन स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के विषय में भी काफी कुछ करने की जरूरत पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। हालांकि भारत ने इस विषय में कुछ मानकों पर अच्छी प्रगति की है, फिर भी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। पूर्व चेतावनी व्यवस्था में सुधार करके आपदाओं में होने वाली हानि को 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। रिपोर्ट में आर्थिक असमानता के चलते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के और ज्यादा चिंताजनक होने की बात कही गई है। जाहिर है कि बढ़ते तापमान का प्रत्यक्ष डंक उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है या जिन्हें दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है, या किसान जिनकी फसल खुले में ईश्वर भरोसे रहती है। उनके लिए जलवायु अनुकूलन व्यवस्था खड़ी करना भी संभव नहीं होता।

बढ़ते तापमान से फसलों की उत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पडऩे के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होने की संभावना बन

सकती है। इस दिशा में जलवायु की विपरीत स्थितियों को झेलने में सक्षम फसलों और फसल किस्मों पर ज्यादा शोध और प्रचार प्रसार की जरूरत है। इस दिशा में पुराने समय में प्रचलित श्री धान्य फसलों कोदा, रामदाना, स्वांक, बाजरा आदि का प्रचार प्रसार करके अच्छी पहल की जा रही है। किन्तु कार्बन उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा उत्पादन तकनीकों और बड़े प्रोजेक्टों, खनन परियोजनाओं के कारण वनों के विनाश से कार्बन प्रचूषण क्षमता में आ रही कमी की चुनौतियां यथावत बनी हैं और बढ़ भी रही हैं। पिछले 15 वर्षों में भारतवर्ष में 3 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग इस तरह की बृहदाकार योजनाओं के लिए बदला जा चुका है और यह क्रम सतत रूप से जारी है। इतनी चिंताजनक स्थिति के बावजूद वर्तमान चुनावों में यह मुद्दा जनता के बीच महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। पर्यावरण से जुड़े दिवसों पर चेतना रैली निकालने, कुछ अच्छे अच्छे नारे लगाने, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने या ज्यादा से ज्यादा चुनाव मैनिफेस्टो में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे उछालने तक हम सीमित होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी जनचेतना जगाने के इस मौके का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आम मतदाता निजी आर्थिक लाभ से ज्यादा सोचने को तैयार नहीं है। इसलिए राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हिमालय के नाजुक परिस्थिति संतुलन के दृष्टिगत यह मामला हिमालय में और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। किन्तु हम प्राकृतिक आपदा का बहाना घड़ कर आत्म संतुष्टि कर लेते हैं या खुद को धोखा देते रहते हैं, जबकि हम सब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित गलतियों का नतीजा है।

फिर भी हम न तो आत्म संयम से अनावश्यक वस्तुओं, पदार्थों के उपयोग से बचना चाहते हैं, न ही सरकारों के सामने अपनी पर्यावरण विषयक चिंताओं को रख कर दबाव बना कर नीतिगत बदलाव की मांग रखना चाहते हैं। सरकारें अपने आप विकास को सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से नाप कर आगे बढ़ती हैं। उन्हें पर्यावरण जैसे मुद्दे उतने लुभावने नहीं लगते। दुनिया भर में सरकारें जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर टालमटोल करते हुए, शर्माते हुए कुछ थोड़ा बहुत कार्य करती रहती हैं। कुछ गंभीरता जब आपदाएं आती हैं तब दिखाई देती है, धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर दोषारोपण करके समस्या भूल जाती है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इस मुद्दे पर कुछ लक्ष्य अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखे हैं। किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर ज्यादा आशा नहीं जगती है। शिमला में 2009 में जलवायु कॉन्क्लेव हुआ था, उसके साथ ही हिमालयी परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए थे, किन्तु दोनों प्रमुख दलों को पर्याप्त समय मिलने के बावजूद विशेष प्रगति इस दिशा में नहीं हो सकी। वैश्विक स्तर और हिमालय के स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौती के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते अब समय आ गया है जब इस मुद्दे पर आम जनता और राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति के केंद्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को रखना चाहिए।

कुलभूषण उपमन्यु
पर्यावरणविद

म, म से मिट्ठू

पीए सिद्धार्थ

झुन्नू लाल के घर से गुजरते हुए मुझे लगा मानो कोई हिंदी की वर्णमाला का अभ्यास कर रहा है। जब ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि सभी अक्षर अपनी पहचान से शुरू हो रहे हैं, पर जब उनसे बनने वाले शब्द बोले जा रहे हैं तो पहला अक्षर 'म' में तबदील हो रहा है जबकि शेष शब्द यथावत हैं। मिसाल के लिए अ से अच्छा होना चाहिए। पर झुन्नू उसे बोल रहे हैं, अ, अ से मच्छा (अच्छा), आ, आ से माम (आम), इ, इ से मिमली (इमली)'। अपनी उत्सुकता दबाने में असफल रहने पर मैं बिना दस्तक उनके घर जा घुसा। मुझे देखते ही उनकी बांछें खिल गईं और बोले, 'अच्छा हुआ महारथी, जो तुम बिन बुलाए चले आए। बुलाने पर तो केवल गंगा पुत्र ही बनारस जाते हैं।' उनके अप्रत्याशित वाक हमले से बचते हुए मैंने एक जिज्ञासु शिष्य की तरह उनकी शरण में जाना बेहतर समझा। जब उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी तो बोले, 'जब देश में पिछले एक दशक से मैं-मैं हो रहा था तब तो तुमने कभी पूछा नहीं। खैर! देर आयद दुरुस्त आयद। किसी ने तो सवाल पूछने की हिम्मत की। चाहे मुझ जैसे अदने इनसान से ही की हो। पर क्या तुम्हें दफ्तर के लिए देर न हो जाएगी?' मैं खींसें निपोरते हुए बोला, 'झुन्नू जी, जब पूरा देश राममय हो रहा है तो डरने की क्या लोड़ है? जिस तरह उत्तम प्रदेश के जौनपुर के एक विश्वविद्यालय में फार्मेसी के छात्र जय श्रीराम लिखकर पास हो गए, उसी तरह मैं भी आज बॉस को गुड मार्निंग की जगह जय श्रीराम बोलकर सीट अपनी पर सीट पर बैठ जाऊंगा।' वह गंभीर होते हुए बोले, 'आपस में हमें इस तरह की सीरियस बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें केवल समारोहों या सम्मेलनों में विचार-विमर्श के लिए होती हैं।'

मैंने अपना प्रश्न पुनः दोहराया कि आपका हर अक्षर अपनी पहचान से शुरू होने के बाद 'म' में क्यों बदल रहा है। वह बोले, 'मुझे पता है कि बिना जाने तुम छोड़ोगे नहीं। सच्चे स्वयंसेवकों की यही पहचान है कि जब एक बार किसी की छाती पर चढ़ जाते हैं तो उसकी सांस उखाड़े बिना हटते नहीं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि देश में बकरियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि चारों ओर मैं-मैं की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। सभी लोग श्रद्धा भाव से तन्मय होकर बड़ी मैं-मैं अपनी मैं-मैं मिला रहे हैं। मुझ पर मैं-मैं का इतना प्रभाव हुआ है कि बीवी को मनाने के लिए जब 'बहारो फूल बरसाओ' गाना शुरू करता हूं तो मुंह से निकलता है 'महारो मूल मरसाओ मेरा महबूब माया है'। आया की जगह माया बोलने पर बीवी शक करती है कि शादी के पच्चीस साल बाद मैं आज भी माया से छिप-छिप कर मिलता हूं।' कहते-कहते वह माया की यादों में खो गए। उनको वापस लाने के भाव से मैंने पुनः निवेदन किया कि जवाब अभी बाकी है। वह सचेत होते हुए बोले, 'अरे हां, बकरी भी मैं-मैं करती है और मि_ भी अपनी ही प्रशंसा करता है। लेकिन मैं-मैं करने वाली लाखों बकरियां हर रोज कसाई के चाकू की धार के नीचे आ जाती हैं। पर मि_ कभी नहीं आता। लोग शान से उसे पिंजरे में अपने घरों में रखते हैं।

आज मैं-मैं इतनी बढ़ गई है कि अब मूर्ख ही राज कर रहे हैं। पर मैं यह फैसला नहीं कर पाया हूं कि देश में संख्या बकरियों की अधिक है या तोतों की। पर मुझे लगता है कि बकरियां मैं-मैं कर रही हैं और तोते उनकी 'मैं-मैं' में अपनी आवाज मिला रहे हैं। कम से कम संवैधानिक संस्थाओं को देखकर तो यही लग रहा है। जहां तक मेरे हर शब्द को म से शुरू करने का प्रश्न है तो देखो, म से मूर्ख, मतदाता, मतदान, मन्दिर-मस्जिद, मुगल, मुसलमान, मटन, मांस, मछली, मंगलसूत्र, माफीनामा वगैरह। माफीनामा से याद आया कि लाला रामदेव झूठ का व्योपार करने के बाद अब कोर्ट से माफी मांग रहे हैं। देखो, जरूरत से ज्यादा मैं-मैं करने पर बात माफी या गरदन तक पहुंच जाती है।'

पीए सिद्धार्थ

सरकार ने अब तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा, पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11 प्रतिशत की आई गिरावट

परिवहन विशेष न्यूज

एफसीआई के सीएमडी अशोक मीणा का कहना है कि गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक हमने 196 लाख टन गेहूं की खरीदारी की है जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की वार्षिक आवश्यकता 186 लाख टन है। हम अपने खरीद लक्ष्यों को प्राप्त करने की सही दिशा में है।

दिल्ली। सरकार ने चालू सीजन के दौरान अब तक 196 लाख टन गेहूं की खरीदारी कर ली है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए जरूरी वार्षिक मांग 186 लाख टन से ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार, अब तक विभिन्न राज्यों के 16 लाख किसानों से 45 हजार करोड़ रुपये के गेहूं की खरीदारी की गई है।

सरकार ने चालू सीजन में 310-320 लाख टन गेहूं की खरीदारी का लक्ष्य रखा है। सरकार के लिए गेहूं की खरीदारी करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष की समान अवधि के 219.5 लाख टन के मुकाबले इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 11 प्रतिशत कम रही है। इसका प्रमुख कारण मध्य प्रदेश और पंजाब में कम खरीदारी होना है।

एफसीआई के सीएमडी अशोक मीणा का कहना है कि गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक हमने 196 लाख टन गेहूं की खरीदारी की है, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की वार्षिक आवश्यकता 186 लाख टन है। हम अपने खरीद लक्ष्यों को प्राप्त करने की सही दिशा में है। इसका कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा से आवक अच्छी है। अकेले इन दोनों राज्यों से 200 लाख टन गेहूं की खरीदारी की जाएगी।

पिछले वर्ष सरकार ने 261.97 गेहूं की खरीदारी की थी। कृषि मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान देश में 1,120.19 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया है। पिछले वर्ष देश में 1,105.54 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।

विदेशी मीडिया भी हुआ भारत के यूपीआई का मुरीद, डिजिटल पेमेंट क्रांति की कर रहा तारीफ

परिवहन विशेष न्यूज

भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का विदेशी मीडिया भी मूरीद हो गया है। हाल में सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस पेटेंट सिस्टम को लेकर आर्टिकल पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में भारत के गांव से लेकर शहरों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की स्वीकार्यता और डिजिटल इकोनॉमी में यूपीआई के योगदान का भी जिक्र भी किया गया है।

नई दिल्ली। दुनियाभर में मौजूद डिजिटल पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने में काफी जटिल हैं। उनके मुकाबले भारत का देसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यह काफी सरल और सुरक्षित है। आज भारत के शहर ही नहीं गांव में भी लोग इसके जरिए जमकर पेमेंट कर रहे हैं। हर रोज इसके चलते करोड़ों रुपये का लेन-देन होता है। देश की गलियों से होता हुआ यूपीआई अब विदेशों में भी जा पहुंचा है। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते विदेशी मीडिया भी इसकी कायल हो गई है।

विदेशी मीडिया हुआ UPI का मुरीद

यूपीआई सिस्टम की तारीफ करते हुए विदेशी मीडिया CNN ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे यह इसने ई-पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी है। इस रिपोर्ट में स्थानीय लोगों और कारोबारियों से बात करते हुए बताया गया कि यूपीआई रियल टाइम फंड ट्रांसजैक्शन की सुविधा देता है। इससे दुकानदार और खरीदार को बहुत आसानी होती है।

रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2047 भारत को विकसित देश बनाने की महत्वाकांक्षा का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने के प्रयासों में ई-पेमेंट सिस्टम की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है।

सीएनएन ने कॉनेल यूनिवर्सिटी में अर्थशात्र के प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद के हवाले से बताया है कि इस ई-पेमेंट सिस्टम की मौजूदा चुनौतियों को कमकर, एफिशिएंसी को बढ़ाकर और लागत को कम करते हुए इसमें और भी वृद्धि की जा सकती है। वे आगे कहते हैं कि यूपीआई और इकोनॉमी के डिजिटलीकरण से विकास में तेजी की संभावना है।

भारत में डिजिटल पेमेंट

भारत में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत इंटरनेट बैंकिंग के साथ करीब 15 साल पहले शुरू हुई थी। शुरू में ई-पेमेंट की रफ्तार काफी धीमी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2016 में भारत में 96 प्रतिशत लेन-देन बैंक नोट के जरिए ही होता था। इसी साल भारत सरकार ने यूपीआई आधारित पेमेंट की शुरुआत की थी। यह पेमेंट सिस्टम ग्राहकों को बैंक डेबिट कार्ड के जरिए मोबाइल एप के जरिए रियल टाइम लेन-देन की सुविधा देता है।

इसी साल के अंत में सरकार ने सभी को चौंकाते हुए देश में मौजूद 500 और 1000 रुपये के बैंक नोट बंद कर दिए थे। इन बैंक नोटों की सर्कुलेशन में कुल हिस्सेदारी करीब 86 प्रतिशत थी। अचानक मार्केट से इतनी बड़ी संख्या में नोट गायब होने का फायदा ई-पेमेंट सिस्टम को मिला। इसके बाद कोविड महामारी के बाद साल 2020 में भी यूपीआई को बढ़ावा मिला।

UPI लेनदेन का हिसाब किताब

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान यूपीआई से कुल 4,912 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इनकी कुल 75.91 लाख करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़कर 8,372 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं, ट्रांजैक्शन की वैल्यू 139.16 लाख करोड़ रुपये हुई। पिछले वित्त वर्ष में तो यूपीआई ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान यूपीआई से 13,113 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 199.95 लाख करोड़ रुपये थी।

ग्लोबल हो रहा यूपीआई

देश ही नहीं बल्कि यूपीआई अब विदेशों में भी पहुंच गया है। फ्रांस का वर्ल्ड फेमस एफिल टावर को देखने की टिकट यूपीआई के जरिए खरीद सकते हैं। फ्रांस के साथ-साथ पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई से लेन-देन शुरू हो चुका है।

यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाले देशों की लिस्ट में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और अरब अमीरात भी शामिल हैं। इसके साथ ही भारत और रूस यूपीआई को लेकर एग्रीमेंट कर चुके हैं। सरकार इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में इस पेमेंट सिस्टम को शुरू करने के लेकर वहां की सरकार से बातचीत कर रही है।

इनसाइड

चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत से ज्यादा रह सकती है विकास दर, NCAER ने जताया अनुमान

इकोनॉमिक थिंक टैंक एनसीएईआर ने कहा कि सामान्य से अच्छे मानसून का अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। जीएसटी संग्रह मार्च में 1.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया जो 2017 में इसके लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। रिपोर्ट में बताया कि साल-दर-साल आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों में वृद्धि को दिखाता है।

नई दिल्ली। अनुकूल वैश्विक परिदृश्य और सामान्य से अधिक मानसून रहने की संभावनाओं के बीच चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर सात प्रतिशत से अधिक रह सकती है। इकॉनामिक थिंक टैंक एनसीएईआर ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा के अप्रैल अंक में कहा है कि मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियां 16 साल के उच्चतम स्तर हैं और यूपीआई लेनदेन रिकार्ड स्तर पर हैं। एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता ने कहा कि समान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान फिर से सात प्रतिशत से अधिक विकास दर हासिल कर सकती है। एनसीएईआर के अनुसार, जीएसटी संग्रह मार्च में 1.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2017 में इसके लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। यूपीआई लेनदेन की बात करें तो मार्च में 13.4 अरब ट्रांजेक्शन हुए।

म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी रोकने के लिए बदलेंगे नियम, मार्केट रेगुलेटर सेबी का बड़ा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

बोर्ड ने वेंचर कैपिटल फंड्स को वैकल्पिक निवेश फंड में स्थानांतरित होने की सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र के लिए संचालन जोखिम प्रबंधन को लेकर संशोधित गाइडेंस नोट जारी किया है। अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को भी इसके दायरे में लाया गया है। एएमसी से संबंधित गड़बड़ी में फ्रंट रनिंग भेदिया कारोबार और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग शामिल हैं।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड ने म्यूचुअल फंड्स से जुड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को शेयरों में फ्रंट-रनिंग और धोखाधड़ी वाले लेनदेन सहित संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान और रोकथाम के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा।

बोर्ड की बैठक के बाद सेबी ने एक बयान में कहा है कि इस तंत्र में उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग व संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग सहित विशिष्ट प्रकार के कदाचार की पहचान, निगरानी और समाधान करने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए।

इसके अलावा बोर्ड ने वेंचर कैपिटल फंड्स को वैकल्पिक निवेश फंड में स्थानांतरित होने की सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र के लिए संचालन जोखिम प्रबंधन को लेकर संशोधित गाइडेंस नोट जारी किया है। अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को भी इसके दायरे में लाया गया है।

सेबी के मुताबिक, संस्थागत तंत्र से एएमसी के कर्मचारियों, डीलरों, स्टॉक ब्रोकरों या किसी अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा संभावित गड़बड़ी का पता लगाने और सूचना देने की उम्मीद की जाती है। इसमें खास तरह की गड़बड़ी की पहचान, निगरानी और पता लगाने के लिए उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और वृद्धि प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए।

एएमसी से संबंधित गड़बड़ी में फ्रंट रनिंग, भेदिया कारोबार और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग शामिल हैं।

जब कोई ब्रोकर या निवेशक गोपनीय जानकारी के आधार पर किसी कारोबार में शामिल होता है, उसे 'फ्रंट रनिंग' कहते हैं। यह ऐसी संवेदनशील जानकारी होती है, जिससे परिसंपत्ति की कीमत प्रभावित होती है।

यह निर्णय सेबी द्वारा एक्सिस एएमसी और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से संबंधित दो 'फ्रंट-रनिंग' मामलों में जारी आदेश के बीच आया है।

आरबीआई ने दो दशक पुराने गाइडेंस नोट को किया अपडेट, बैंकों और NBFC पर होगा सीधा असर

परिवहन विशेष न्यूज

रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के लिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर अपने गाइडेंस नोट को अपडेट किया है और इसका दायरा आवास वित्त कंपनियों सहित NBFC तक भी बढ़ा दिया। 2005 के ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर गाइडेंस नोट में केवल कॉमर्शियल बैंकों शामिल थे। आइए जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने यह फैसला क्यों लिया और इसका क्या असर होगा।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को वित्तीय क्षेत्र के लिए ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर अपने 'गाइडेंस नोट' को अपडेट किया है और इसका दायरा आवास वित्त कंपनियों सहित NBFC तक भी बढ़ा दिया। 2005 के 'ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर गाइडेंस नोट' में केवल कॉमर्शियल बैंकों शामिल थे।

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि परिचालन संबंधी व्यवधान किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी (आरई) के वजूद को खतरे में डाल सकता है। उसके ग्राहकों और अन्य बाजार सहभागियों को प्रभावित कर सकता है। आखिर में उसका वित्तीय स्थिरता पर काफी बुरा असर पड़ता है।

इन गड़बड़ियों से मुकाबला

परिचालन से जुड़ी गड़बड़ी का कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई मानवीय वजह, आईटी से जुड़े खतरे, भू-राजनीतिक संघर्ष, व्यापार में व्यवधान, आंतरिक या बाहरी धोखाधड़ी, थर्ड पार्टी पर निर्भरता या फिर कोई कुदरती कारण। आरबीआई के गाइडेंस नोट का मकसद किसी भी रेगुलेटेड संस्था में रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करना है, ताकि ऐसी समस्याओं का संस्था और ग्राहकों पर कम से कम असर हो।

जैसे कि अगर कोई रेगुलेटेड संस्था किसी थर्ड पार्टी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है, तो यह उसके लिए सही नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई भी मसला होता है, तो इससे रेगुलेटेड एंटिटी का भी कामकाज पड़ सकता है। इसलिए गाइडेंस नोट में बताया जाएगा कि इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटा जाए।

गाइडेंस नोट में बदलाव

अपडेट गाइडेंस नोट के मुख्य बदलावों में से एक यह भी है कि अब इसका दायरा कॉमर्शियल बैंकों के साथ ही सभी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी बैंकों तक बढ़ा गया है। केंद्रीय बैंक ने 2005 के गाइडेंस नोट को निरस्त कर दिया है, जो केवल कॉमर्शियल बैंकों पर लागू था। नए नोट के सेफ्टी मॉडल में चरण हैं, जिनसे वित्तीय संस्थान में गड़बड़ी के जोखिम को कम किया जाएगा।

किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बना प्याज, निर्यात की मंजूरी तो मिली, लेकिन...

परिवहन विशेष न्यूज

देश में इस बार लगभग 800 लाख टन प्याज उत्पादन का अनुमान है। ऐसे में सिर्फ 99 हजार टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसानों की मांग है कि कम से कम 15 लाख टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दी जाए। पिछले वर्ष प्याज की खरीफ और रबी दोनों का कम उत्पादन हुआ था जिसके चलते दाम बढ़ने लगा था।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जब प्याज के दाम आसमान चढ़ रहे थे तो उपभोक्ताओं की जेब हल्की हो रही थी। अब नई फसल के आने के बाद खुले बाजार में प्याज की गिरती कीमतों ने किसानों को बेचैन कर रखा है। केंद्र सरकार ने पांच माह से प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाकर काफी हद तक किसानों को राहत देने का प्रयास किया है। यद्यपि इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि किसानों को साधने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

केंद्र ने दो दिन पहले छह देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मारीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इसके साथ ही केंद्र ने मध्य-पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के बाजारों के लिए विशेष रूप से उपजाए गए दो हजार टन सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। किसान इसे नाकाफी मान रहे हैं।

इस साल प्याज की बंपर फसल का अनुमान

देश में इस बार लगभग 800 लाख टन प्याज उत्पादन का अनुमान है। ऐसे में सिर्फ 99 हजार टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसानों की मांग है कि कम से कम 15 लाख टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दी जाए। पिछले वर्ष प्याज की खरीफ और रबी दोनों का कम उत्पादन हुआ था, जिसके चलते दाम बढ़ने लगा था। केंद्र सरकार ने बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिए पिछले आठ दिसंबर को निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। यह अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही थी, किंतु चुपचाप इसे आगे बढ़ा दिया गया।

सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है उत्पादन

देश में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इस बार भी बंपर उत्पादन हुआ है। ऐसे में निर्यात पर प्रतिबंध के चलते घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ गई और कीमत लगातार गिरने लगी। उपभोक्ताओं के लिए तो यह राहत की बात है, लेकिन किसानों की परेशानी यहीं से शुरू हो गई। पर्याप्त भंडारण की समस्या के कारण किसान अपनी फसल को औने-पौने कीमत में बेचने पर मजबूर होने लगे। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात की अनुमति देकर किसानों एवं उपभोक्ताओं में संतुलन साधने का प्रयास किया है।

पांच लाख टन प्याज का भंडारण

मूल्य नियंत्रण कोष के तहत केंद्र सरकार ने रबी प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य इस वर्ष पांच लाख टन निर्धारित किया है। केंद्रीय खरीद एजेंसियां भंडारण योग्य प्याज की खरीद शुरू करने के लिए एफपीओ समेत अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। शीतगृहों एवं स्टाक में भंडारण के दौरान प्याज के होने वाले नुकसान को घटाकर दस प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।

वैक्सीन के बाद भारत की प्याज डिप्लोमेसी, सिर्फ चुनिंदा देशों को ही क्यों कर रहा निर्यात?

भारत ने पिछले करीब पांच महीने से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिर भी उसने 6 देशों को प्याज भेजने अनुमति दे दी है। वहीं महंगी मानी जाने वाली सफेद प्याज भी मिडल-ईस्ट और कुछ यूरोपीय देशों को निर्यात की जा रही है। आइए जानते हैं कि सरकार देश में प्याज के बढ़ते दाम के बीच निर्यात की इजाजत क्यों दे रही है।

नई दिल्ली। भारत ने पिछले करीब पांच महीने से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिर भी उसने 6 पड़ोसी देशों को प्याज भेजने मंजूरी दे दी है। वहीं, महंगी मानी जाने वाली सफेद प्याज भी मिडल-ईस्ट और कुछ यूरोपीय देशों को निर्यात की जा रही है। भारत का चुनिंदा देशों को प्याज निर्यात करना इसलिए भी अहम है, क्योंकि भारत में इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों जारी हुए थोक महंगाई के आंकड़ों में भी यह चीज साफ दिखी। इसमें आलू के साथ प्याज के भाव में भी 50 प्रतिशत से अधिक इजाफा देखा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार चुनावी सीजन के दौरान देश में प्याज का दाम बढ़ने का जोखिम उठाकर भी निर्यात में क्यों ढील दे रही है? क्या यह सरकार की प्याज डिप्लोमेसी है? इससे क्या हासिल होगा? आइए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सरकार ने 6 देशों- बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है। ये सभी देश भारत के पड़ोसी हैं और इनकी सामरिक और रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। इनके साथ भारत के कारोबारी संबंध भी काफी समृद्ध हैं।

कम वोटिंग और 'नोटा' को मान्यता की मांग

दो चरणों के शुरुआती दौर में कम मतदान से 'कहीं खुशी कहीं गम' का माहौल है। कम हो रहे मतदान का मर्ज दरअसल कुत्सित राजनीति और अवसरवादी नेताओं के प्रति जनता का अविश्वास प्रस्ताव है।

दो चरणों के शुरुआती दौर में कम मतदान से 'कहीं खुशी कहीं गम' का माहौल है। कम हो रहे मतदान का मर्ज दरअसल कुत्सित राजनीति और अवसरवादी नेताओं के प्रति जनता का अविश्वास प्रस्ताव है। जनता के गुस्से, क्षोभ और अरुचि को समझने की बजाय, चुनाव आयोग पानी में लाठी मारकर समाधान का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कई कस्बों में जागरूकता बढ़ाने के नाम पर चुनाव आयोग वाहनों के काफिले से रोड शो कर रहा है। ऐसे भद्दे रोड शो में बढ़ रहे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और लाऊड स्पीकर के ध्वनि प्रदूषण से चुनावों के प्रति लोगों की रही-सही रुचि भी कम हो रही है।

वोट नहीं देने का कानूनी हकः संविधान के तहत 18 साल से बड़ी उम्र के भारतीय नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए लेकिन अनिवार्य वोटिंग के बारे में फिलहाल कोई कानून नहीं है। साल 1961 में बनाए गए चुनावी नियम 49-ओ में वोट नहीं डालने के अधिकार का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में लिली थॉमस मामले में कहा था कि लोगों को वोट नहीं देने का भी अधिकार है। ई.वी.एम. से वोटिंग शुरू होने के बाद साल 2013 में सुप्रीमकोर्ट के फैसले से लोगों को नोटा का विकल्प भी हासिल हो गया। वह फैसला पी.यू.सी.एल. मामले में चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम, रंजना देसाई और रंजन गोगोई की बैंच ने दिया था। ई.वी.एम. से नोटा का विकल्प चुनने पर मतदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहती है जो पुराने नियमों में सम्भव नहीं था। सभी उम्मीदवारों को असंतोषजनक मानने की स्थिति में वोटर नोटा का बटन दबाकर उन्हें अस्वीकार कर सकता है।

साल 2019 में बिहार के गोपालगंज में 51,660 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। पिछले 5 सालों में लगभग 1.29 करोड़ लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। मौजूदा कानून के अनुसार नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलें तो भी चुनाव परिणाम में फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीमकोर्ट के फैसले अनुसार नोटा के बाद चुनावों में बेहतर उम्मीदवार के चयन से लोकतंत्र मजबूत होगा लेकिन पक्ष और विपक्ष के नेताओं के भाषणों और आरोपों से साफ है कि दलों के दलदल में चुनावी व्यवस्था का कैंसर बढ़ता जा रहा है। पैसे और शराब के दम पर रैलियों और रोड शो में भीड़ के प्रचलन में कोई कमी नहीं आ रही। सत्ता हासिल करने के लिए सभी तरह के सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं लेकिन सरकारों की खाली तिजोरी की हकीकत सामने नहीं आ रही।

इन चुनावों में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद है जिसमें से अधिकांश भ्रष्टाचार से अर्जित काला धन है। इसके खर्चे का पार्टियों और चुनाव आयोग के पास कोई हिसाब-किताब नहीं है। चुनावी भाषणों में लगाए जा रहे सभी आरोपों पर कानूनी तौर पर संज्ञान लिया जाए तो सभी दलों के नेताओं के खिलाफ लाखों एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिएं। चुनावी नतीजों के बाद भ्रष्ट और दल-

बदलू नेताओं से बनी किसी भी सरकार से लोगों को बदलाव और सुशासन की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह से पोङ्कषलग बूथ जाने में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है।

नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार की मान्यता : सुप्रीमकोर्ट ने ई.वी.एम. और वी.वी.पैट की वैधता पर फिर से मोहर लगाई है। उसी दिन चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ की दूसरी बैंच ने नोटा को प्रत्याशी मानने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस याचिका में नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार का दर्जा देने की मांग की गई है। सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और निर्दलीय उम्मीदवारों की नाम वापसी के बाद भाजपा उम्मीदवार निर्ववरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसके पहले सपा नेता डिम्पल यादव, कांग्रेस नेता वाई.वी. चह्वाण, फारूक अब्दुल्ला समेत कई दलों के 35 नेता निर्ववरोध जीत चुके हैं।

अरुणाचल प्रदेश में तो भाजपा के 10 विधायक निर्ववरोध जीत गए थे। सिर्फ एक प्रत्याशी के रहने पर निर्ववरोध निर्वाचन के लिए आर.पी. एक्ट की धारा-53 (3) में प्रावधान है। इस बारे में चुनाव आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए अगस्त, 2023 में जारी हैंडबुक में विस्तार से प्रावधान किए हैं। सुप्रीमकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार निर्ववरोध जीतने से लोगों के वोट डालने के अधिकार का हनन होता है।

याचिकाकर्ता शिव खेड़ा के अनुसार महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुड्डुचेरी में राज्य निर्वाचन आयोग के बनाए गए नियमों के अनुसार नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने पर पुनर्मतदान होना चाहिए। इसलिए इस तरह की व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में पूरे देश में होनी चाहिए। नोटा की व्यवस्था सुप्रीमकोर्ट के फैसले से लागू हुई थी और इसके लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया। राज्यसभा चुनावों में नोटा की व्यवस्था लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने जनवरी, 2014 और नवम्बर 2015 में आदेश जारी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद-80 (4) और आर.पी. एक्ट की व्याख्या करते हुए चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया। उस फैसले में व्हिप को भी नए सिरे से मान्यता मिलने की वजह से पार्टियों के विधायकों का दर्जा बंधुआ से भी बदतर हो गया।

नोटा को व्यावहारिक मान्यता देने में कई कानूनी बाधाएं हैं। न्यूनतम वोटिंग के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। साल 2018 में स्थानीय निकाय चुनावों में श्रीनगर में 2.3 प्रतिशत से कम लोगों ने वोट दिया था। उसके बाद मई, 2019 के लोकसभा चुनावों में शोपियां और पुलवामा में 2.81 से 10.3 प्रतिशत वोट ही डाले गए थे। चपरासी की नौकरी के लिए न्यूनतम शिक्षा और नर्सरी के विद्यार्थी को पास होने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत नम्बरों का नियम है लेकिन नेताओं के लिए शिक्षा और चुनावों में न्यूनतम वोट हासिल करने के लिए कोई नियम नहीं है।

याचिकाकर्ता ने नियमों में बदलाव करने के लिए सुप्रीमकोर्ट से मांग की है लेकिन संसद में आर.पी. एक्ट कानून में संशोधन के बगैर नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिलना मुश्किल है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और जनता के आक्रोश को व्यक्त करने के लिए नोटा का प्रावधान किया गया था। इसलिए नोटा में डाले गए वोट यदि हार-जीत के अंतर से ज्यादा हों तो चुनाव रद्द होना ही चाहिए। नोटा को सार्थक मान्यता के बाद ही 'राइट टू रिजैक्ट' और 'राइट टू रिकॉल' के अधिकारों के कानून पर बात आगे बढ़ेगी। इन चुनावी सुधारों और कानूनों से नेताओं की जवाबदेही बढने के साथ लोगों का चुनावों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा।

-विराग गुप्ता
(एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट)

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर : डीओए, सीएनआई, एचआईवी- एड्स और नशा पीड़ितों की पहचान और मदद करने के प्रयासों को बढ़ाएगी

परिवहन विशेष न्यूज

डोगर गाँव में किया स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित

अमृतसर, (साहिल बेरी) एचआईवी-एड्स और नशा पीड़ितों और उनके परिवारों द्वारा उन पर जताए गए भरोसे से प्रोत्साहित होकर, डायोसिस ऑफ अमृतसर (डीओए), चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई), अपने नशा-विरोधी और एचआईवी-एड्स जागरूकता अभियान को उसके दायरे में आने वाले सीमावर्ती इलाकों में और तीव्र करेगी। डायोसिस ने इस आशय हेतु डोगर गाँव में टर्निंग पॉइंट नामित अपने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया।द मोस्ट रेव डॉ. पी.के. सामंताराय, बिशप, डायोसिस ऑफ़ अमृतसर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई), के तत्वावधान के अधीन आयोजित इस शिविर का संचालन फतेहगढ़ चूड़ियाँ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने किया। इस दौरान क्षेत्र के निवासियों को मुफ्त चिकित्सा जांच प्रदान की गई।

डायोसिस क्षेत्र में एचआईवी-एड्स और नशे के दानव से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन क्षेत्रों को हमने कवर किया उनमें नशे के दुरूपयोग में कमी आने की कुछ बहुत ही स्वागतयोग्य रिपोर्टें हमें प्राप्त हुई हैं। हम जनता की भलाई के लिए अधिक स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके अपने प्रयासों को तीव्र करने का इरादा रखते हैं," द मोस्ट रेव डॉ पी के सामंताराय, बिशप, डायोसिस ऑफ अमृतसर (डीओए), सीएनआई ने कहा।

इस मौके पर डायोसिस ने जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त दवाएँ भी वितरित कीं। श्रीमती सोनिया सामंताराय, विकास अधिकारी, डीओए, सीएनआई, ने रेव पवन पॉल, डॉ एल्मा राम और अन्य कार्यकर्ताओं की मदद से इस शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर रेव लिली सामंताराय, श्री डेनियल बी दास, श्री ओम प्रकाश, रेव अयूब डेनियल, रेव डॉ पुलक सामंताराय, रेव मृणाल सेनगुप्ता भी उपस्थित थे।

तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 15 मई तक निलंबित...

Air India Tel Aviv पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एअर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। विमानन कंपनी ने 19 अप्रैल को कहा था कि तेल अवीव के लिए उसकी उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी। यह दिल्ली और इजरायली शहर के बीच चार साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है।

दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एअर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। विमानन कंपनी ने 19 अप्रैल को कहा था कि तेल अवीव के लिए उसकी उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी। यह दिल्ली और इजरायली शहर के बीच चार साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है।

एयरलाइन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच तेल अवीव के लिए आने-जाने वाली उड़ानों का निलंबन 15 मई तक बढ़ा दिया है।

स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं- एअर इंडिया

एअर इंडिया ने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अपने उन यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने इस दौरान तेल अवीव की यात्रा के लिए टिकट ली हुई है।

टिकट रद्द कराने को लेकर शुल्क पर एक बार की छूट दी

इन यात्रियों को नई तारीख निर्धारित करने और टिकट रद्द कराने को लेकर शुल्क पर एक बार की छूट दी गई है। इजरायली शहर पर हमास समूह के हमले के बाद एअर इंडिया ने सात अक्टूबर, 2023 से तेल अवीव के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थीं। इजरायल और हमास समूह संभावित संघर्ष विराम पर भी बातचीत कर रहे हैं।

कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों के लिए कितनी चिंता की बात? भारत कर रहा वैक्सीन के साइड इफेक्ट की निगरानी

कोरोना वैक्सीन (Covid Vaccine) कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर लंदन की कंपनी आस्ट्राजेनिका की स्वीकारोक्ति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है । स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आस्ट्राजेनिका के पूरे हलफनामे में दिए गए तथ्यों को जानना जरूरी है। बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर कोरोना रोधी टीकाकरण में इस्तेमाल किया गया था।

नईदिल्ली। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर लंदन की कंपनी आस्ट्राजेनिका की स्वीकारोक्ति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले आस्ट्राजेनिका की लंदन में अदालत में दिये गए पूरे हलफनामे को देखना चाहता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूरी दुनिया में सक्रिय वैक्सीन विरोधी लाबी का हवाला देते हुए कहा कि आस्ट्राजेनिका के पूरे हलफनामे में दिए गए तथ्यों को जानना जरूरी है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की भारत में दो स्तरों पर निगरानी की जा रही है, लेकिन इनमें खून के थक्के जमने वाली दुर्लभ बीमारी थ्रोंबोसिस विथ थ्रोंबोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के गंभीर मामले सामने नहीं आए हैं।

भारत में बढ़ी चिंता

भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर कोरोना रोधी टीकाकरण में इस्तेमाल किया गया था। दरअसल कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर लंदन की अदालत में चल रहे केस के जवाब में इसे विकसित करने वाली कंपनी आस्ट्राजेनिका ने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में टीटीएस के लक्षण दिखा है। यह भारत समेत पूरी दुनिया में कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों में चिता का सबब बनना स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव के बीच हुए इस खुलासे को लेकर मंत्रालय के अधिकारी आधारिक रुप से कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आस्ट्राजेनिका के अदालत में दिए हलफनामे को जल्द हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई है। एक बार हलफनामा देखने के बाद ही इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय रख रहा पैनी नजर

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की निगरानी की दोहरी प्रणाली है, जो आज भी काम कर रही है। एक तरफ आइसीएमआर के विशेषज्ञों की टीम इसका अध्ययन करती है, तो दूसरी ओर चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशालय (डीजीएचएस) भी जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी करता है। डीजीएचएस की देश भर में शाखाएं हैं। आइसीएमआर और डीजीएचएस दोनों में से किसी ने भी अभी तक किसी भी कोरोना वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट के गंभीर मामलों की रिपोर्ट नहीं दी है।

मुख्यमंत्री नबीन पटनायक बिधानसभा सीट केलिया हिंजिलिकाटू से अपना नामांकन दाखिल किया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वरः मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज (30 अप्रैल) हिंजिलिकातु विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके साथ 5 चेयरमैन वीके पांडियन, बरहामपुर लोकसभा प्रत्याशी भृगु बक्सीपात्रा और मंत्री विक्रमकेशरी अरुख मौजूद थे ।20 मई को इस सीट पर दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि नवीन यहां से छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं ।उन्होंने आवेदन पत्र जिला प्रमुख छत्रपुर के कार्यालय में जमा कर दिया है । मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे छत्रपुर के पास नरसिंहपुर स्ट्रीट स्थित हेलीपैड पर उतरे। वहां से वह कार से अपनी मां की दरगाह पर गए और पूजा करने के बाद छत्रपुर उपजिलापाल के कार्यालय पहुंचे और याचिका दायर की। उधर, मुख्यमंत्री के नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किये गये हैं । कल आईजी साउथ रीजन जयनाराण पंकज और एसपी गंजाम। जगमोहन मीना ने अस्थायी हेलीपैड क्षेत्र, छत्रपुर उपजिलापाल कार्यालय और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

शाह के फेक वीडियो पर भड़के नड्डा, INDI गठबंधन की राजनीति के स्तर पर उठाए सवाल

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो पर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई के राजनीति के स्तर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल एक डीपफेक वीडियो प्रसारित करने में शामिल हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन कर रही है जबकि संविधान के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता।

शिमोगा। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो पर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई के राजनीति के स्तर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल एक डीपफेक वीडियो प्रसारित करने में शामिल हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन कर रही है जबकि संविधान के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पर 'धूर्त और विभाजनकारी मंसूबे' रखने का आरोप लगाया। वह शिमोगा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बी.वाई. राघवेंद्र के लिए भाजपा के प्रचार अभियान के तहत यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मीडिया ने विपक्षी के डीप फेक वीडियो का पर्दाफाश किया

उन्होंने कहा, 'विपक्षी एक फर्जी वीडियो लेकर आए, पर लोगों और मीडिया ने विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के डीप फेक वीडियो का पर्दाफाश किया। इसका दुखद हिस्सा यह है कि फर्जी वीडियो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के फोन से इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया गया था और 'आईएनडीआईए' गठबंधन के सभी सहयोगियों ने इसे वायरल करने की कोशिश की।'

400 सीटें पार करने को लेकर गहरे अवसाद में विपक्ष

नड्डा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा और राजग के 400 सीटें पार करने को लेकर गहरे अवसाद में हैं। नड्डा ने कहा, 'संविधान में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि धार्मिक आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने (कांग्रेस) क्या किया (कर्नाटक में) ओबीसी कोटा से मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया।' उन्होंने दावा किया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस चार बार कानून लेकर आई, जिसके जरिये उसने एससी/एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समुदाय को देने की कोशिश की।

हम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'हम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, लेकिन ये लोग (कांग्रेस) धूर्त और विभाजनकारी मंसूबे रखते हैं।' विपक्षी दलों पर 'विभाजनकारी राजनीति' में शामिल होने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा, 'कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था और वे यह धारणा और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा एससी/एसटी और ओबीसी के खिलाफ है और अगर हम (भाजपा) सत्ता में आते हैं तो इन समुदायों के लिए आरक्षण खत्म हो जाएगा।'

कर्नाटक के हावेरी में भाजपा अध्यक्ष ने किया रोड शो

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को हावेरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार बसवराज बोम्मई के समर्थन में यहां बयादागी में एक रोड शो किया। विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर भाजपा नेता ने सड़क के दोनों ओर व इमारतों पर एकत्र लोगों का अभिवादन किया और हाथ हिलाया। इस दौरान कई लोगों को 'मोदी, मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते देखा गया। जब उनका काफिला यहां गुटेम्मा मंदिर से सुभाष सर्कल की तरफ बढ़ा तो लोगों ने पुष्प वर्षा की। नड्डा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई, कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक समेत अन्य लोग मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023